



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1977/वैशाख 3, 1899
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977/VAISAKHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1977

का० आ० 1161—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत निर्वाचन आयोग तमिलनाडु सरकार के परामर्श से श्री एम० पी० श्रीनिवासन के स्थान पर श्री सी० के० आशा, आई० ए० एस० को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक तमिलनाडु राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/तमिलनाडु/77]
प्र० कु० मिश्र, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 1st April, 1977

S.O. 1161.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with Government of Tamil Nadu, hereby nominates Shri D. K. Oza, IAS, as Chief Electoral Officer for the State of Tamil Nadu, with effect from the date he takes charge of the office and until further orders vice Shri S. P. Srinivasan.

[No. 154/TN/77]
P. K. MISRA, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नोटिस

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1977

का० आ० 1162—इसके द्वारा लेख्य प्रमाणक नियम (नोटरीज रूलस) 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री बन्सीधर राव एडवाकेट, बीदार (कर्नाटक) ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, बीदार में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियाँ हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशन होने के चौबह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाएँ।

[संख्या 22/31/76 न्याय]

प्रार० वामुदेवन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 6th April, 1977

S.O. 1162.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Bansidhar Rao, Advocate Bidar (Karnataka) for appointment as a Notary to practise in Bidar.

(1411)

2 Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F 22/31.76-Jus]

R. VASUDHARAN, Dy. Secy.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1977

क्र० आ० 1163—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राय बरेली क्षेत्र ग्रामीण बैंक, राय बरेली के अध्यक्ष के रूप में श्री श्याम चन्द्र मोनी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. एफ० 1/92/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च 1977” शब्दों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” शब्द, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एफ० 4-92/75-ए० सी०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(BANKING WING)

New Delhi, the 31st March, 1977

S.O. 1163.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks, Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-92/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri Shyam Chandra Moni as the Chairman of the Ray Bareilly Kshetriya Gramin Bank, Ray Bareilly, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words “31st March 1977” the figures, letters and words “30th September, 1977” shall be substituted

[No. F 4-92/75-AC]

क्र० आ० 1164—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मगध ग्रामीण बैंक, गया के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० के० प्रसाद की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. एफ० 1-92/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च, 1977” शब्दों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” शब्द, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एफ० 4-80/76-ए० सी०]

S.O. 1164 - In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks, Act 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-80/76-AC, dated the 10th November, 1976 relating to the appointment of Shri R. K. Prasad as the Chairman of the Magadh Gramin Bank, Gaya, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words “31st March 1977” the figures, letters and words “30th September, 1977” shall be substituted.

[No. F. 4-80 76-AC]

क्र० आ० 1165—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रताप चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. एफ० 4-94/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च 1977” शब्दों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” शब्द, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एफ० 4-94/75-ए० सी०]

S.O. 1165.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-92/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri Pratap Chakraborty as the Chairman of the Mallabhum Gramin Bank, Bankura, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words “31st March 1977” the figures letters and words “30th September, 1977” shall be substituted.

[No. F. 4-94/75-AC]

क्र० आ० 1166—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी के अध्यक्ष के रूप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. एफ० 4-69/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च, 1977” शब्दों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” शब्द, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एफ० 4-69/75-ए० सी०]

S.O. 1166—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-69/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment

of Shri Shiv Sharma as the Chairman of the Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977", the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-69 75-AC]

का० आ० 1167.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हरियाणा ग्रामीण बैंक, भिवानी के अध्यक्ष के रूप में श्री एम० के० खन्ना की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4/11-75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" अको, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" अक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-11/75-ए० सी०]

S.O. 1167.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-14/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri S. K. Khanna as the Chairman of the Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977", the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-14/75-AC]

का० आ० 1168.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मारवाड़ ग्रामीण बैंक पाली के अध्यक्ष के रूप में श्री बलराम मिश्र की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 6 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-82/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" अकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" अक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-82/76-ए० सी०]

S.O. 1168.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-82/76-AC, dated the 6th September, 1976 relating to the appointment of Shri Balram Mishra as the Chairman of the Marwar Gramin Bank, Pali, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-82/76-AC]

का० आ० 1169.—प्रादेशिक बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री विद्याधर ग्रामीण बैंक, श्री काकुलम के अध्यक्ष के रूप में श्री डी० आर० के० पटनायक की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-84/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" अको, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" अक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-84/76-ए० सी०]

S.O. 1169.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-84/76-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri D. R. K. Patnaik as the Chairman of the Sri Visakha Gramina Bank, Srikakulam, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-84 76-AC]

का० आ० 1170.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० सी० बुधिराजा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-85/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977", अको, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" अक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-85/75-ए० सी०]

S.O. 1170.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-85/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri R. C. Budhiraja as the Chairman of the Guigaon Gramin Bank, Gurgaon, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-85/75-AC]

का० आ० 1171.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री के० डी० अग्रवाल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की

दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-13/75-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च, 1977” अंक, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-13/75-ए०सी०]

S.O. 1171.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-13/75-AC, dated 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri K. D. Agrawal, as the Chairman of the Gorakhpur Ksbetriya Gramin Bank, Gorakhpur, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words “31st March, 1977” the figures, letters and words “30th September, 1977” shall be substituted.

[No. F. 4-13/75-AC]

क्र० आ० 1172.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उ० प्र०) के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० एन० राय की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 16 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-58/76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च, 1977” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-58/76-ए०सी०]

S.O. 1172.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F-4-58/76-AC, dated the 16th September, 1976 relating to the appointment of Shri B. N. Rai as the Chairman of the Bhagirath Gramin Bank, Sitapur (U.P.), namely :

In the said notification, for the figures, letters and words “31st March, 1977” the figures, letters and words “30th September, 1977” shall be substituted.

[No. F. 4-58/76-AC]

क्र० आ० 1173.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगीर के अध्यक्ष के रूप में श्री गोलक बिहारी सारंगी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-86/75-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च, 1977” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-86/75-ए०सी०]

S.O. 1173.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-86/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri Golak Bihari Sarangi as the Chairman of the Bolangir Anchalik Gramya Bank, Bolangir, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words “31st March, 1977” the figures, letters and words “30th September, 1977” shall be substituted.

[No. F. 4-86/75-AC]

क्र० आ० 1174.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा के अध्यक्ष के रूप में श्री दलीप मुखर्जी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-11/75-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च, 1977” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-11/75-ए०सी०]

S.O. 1174.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-11/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri Dilip Mukherjee as the Chairman of the Gaur Gramin Bank, Malda, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words “31st March, 1977” the figures, letters and words “30th September, 1977” shall be substituted.

[No. F. 4-11/75-AC]

क्र० आ० 1175.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० जी० बालगोपाल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 2 अक्टूबर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-86/76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के “31 मार्च, 1977” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 1977” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-86/76-ए०सी०]

S.O. 1175.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-86/76-AC, dated the 2nd October, 1976 relating to the appointment of Shri H. G. Balagopal as the Chairman of the Cauvery Gramina Bank, Mysore, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-86/76-AC]

का०आ० 1176—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कोरापुट पंचायती ग्राम्य बैंक, जयपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० नायक की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 13 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-88/76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-88/76-ए०सी०]

S.O. 1176.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking (Banking Wing) No. F. 4-88/76-AC, dated the 13th November, 1976 relating to the appointment of Shri P. Nayak as the Chairman of the Koraput-Panchabati Gramya Bank, Jeypore, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977", the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-88/76-AC]

का०आ० 1177—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा खिलामपुर, रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खिलामपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० एम० शर्मा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 20 अक्टूबर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-79/76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित करती है।

[सं० एफ० 4-79/76-ए०सी०]

S.O. 1177.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-79/76-AC, dated the 20th October, 1976 relating to the appointment of Shri H. M. Sharda as the Chairman of the Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, Bilaspur, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-79/76-AC]

का०आ० 1178.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कटक ग्राम्य बैंक, कटक

के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वरूप चन्द्र दास की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-76/76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित करती है।

[सं० एफ० 4-76/76-ए०सी०]

S.O. 1178.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. 4-76/76-AC, dated the 11th October, 1976 relating to the appointment of Shri Swarup Chandra Dash as the Chairman of the Cuttack Gramya Bank, Cuttack, namely :

In the said notification, for the figures, letters, and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-76/76-AC]

का०आ० 1179—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम के अध्यक्ष के रूप में श्री एन० मधुसूदन बाबू की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 10 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-67/75-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" श्रृंखला, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-67/75-ए०सी०]

S.O. 1179.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-67/75-AC, dated the 10th November, 1976 relating to the appointment of Shri N. Madhura Babu as the Chairman of the Nagarjuna Gramins Bank, Khammam, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-67/75 AC]

का०आ० 1180.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री एम०बी० नन्द खन्ना की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ० 4-90/75-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के '21 मार्च, 1977' अर्थात् अक्षर और शब्द के स्थान पर '30 सितम्बर, 1977' अर्थात् अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एक. 4-90/77-ए.सी.]

S.O. 1180—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 490/75 AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri Raghbir Chand Khanna as the Chairman of the Farukhabad Gramin Bank, Farukhabad, namely

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted

[No. F. 490/75 AC]

कां.आ. 1181—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 31 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, कन्द्रीय सरकार एतद्वारा बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी के अध्यक्ष के रूप में श्री कुंवर खोरेन्द्र सिंह गुप्ता की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) को दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. एक. 4-93/77-ए.सी. में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के '31 मार्च, 1977' अर्थात् अक्षर और शब्द के स्थान पर '30 सितम्बर, 1977' अर्थात् अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एक. 4-93/77-ए.सी.]

S.O. 1181—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 493/75 AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri Kanwar Vuendia Singh Gupta as the Chairman of the Barabanki Gramin Bank, Barabanki, namely

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977", the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted

[No. F. 493/75 AC]

कां.आ. 1182—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 31 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, कन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्रथमा बैंक, मुरादाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री एम. आर. वस्तगीर की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) को दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. एक. 4-15/76-ए.सी. में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" अर्थात् अक्षर और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" अर्थात् अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एक. 4-15/76-ए.सी.]

S.O. 1182—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 415/75 AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri S. R. Dasgupta as the Chairman of the Prathama Bank, Muradabad, namely

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted

[No. F. 415/75 AC]

कां.आ. 1183—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 31 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, कन्द्रीय सरकार एतद्वारा सम्युक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आज़मगढ़ के अध्यक्ष के रूप में श्री हसन कदवाई की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) को दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. एक. 4-91/75-ए.सी. में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के '31 मार्च, 1977' अर्थात् अक्षर और शब्द के स्थान पर '30 सितम्बर, 1977' अर्थात् अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एक. 4-91/75-ए.सी.]

S.O. 1183—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 491/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri Hasan Kidwai as the Chairman of the Samyukt Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh, namely—

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted

[No. F. 491/75-AC]

कां.आ. 1184—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, कन्द्रीय सरकार एतद्वारा शेखवाटी ग्रामीण बैंक, सीकर के अध्यक्ष के रूप में श्री आर. जी. पुरी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) को दिनांक 7 अक्टूबर, 1976 की अधिसूचना सं. एक. 4-91/76-ए.सी. में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" अर्थात् अक्षर और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" अर्थात् अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. एक. 4-91/76-ए.सी.]

S.O. 1184—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 491/76-AC, dated the 7th October, 1976 relating to the appointment of Shri R. G. Puri as the Chairman of the Shekhawati Gramin Bank, Sikar, namely—

In the said notification, for the figures, letters and words "21st March, 1977" the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted

[No. F. 481/76-AC]

कां०अ० 1185—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) का प्राग 11 के साथ पठित प्राग 11 के प्राग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, जयपुर नगरी प्राचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एम. एन. जैन की नियुक्ति विषय भारत सरकार, राज्य और वैयक्तिक विभाग (वैयक्तिक पक्ष) की दिनांक 30 सितम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० एफ 4-12/75-ए०सी० में विनिर्दिष्टा संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के "31 मार्च, 1977" शब्दों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "30 सितम्बर, 1977" शब्द, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-12/75-ए०सी०]

सी०आर० बिस्वास उप सचिव

S.O. 1185—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-12/75-AC, dated the 30th September, 1976 relating to the appointment of Shri S. L. Jain as the Chairman of the Jipur Nagaur Anchalik Gramin Bank, Jaipur, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1977", the figures, letters and words "30th September, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-12/75-AC]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1977

कां०अ० 1186—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 9 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री जी० लक्ष्मीनारायण को, 1 अप्रैल, 1977 से प्रारम्भ होकर 30 अप्रैल, 1977 को समाप्त होने वाली और अवधि के लिये इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/3/77-बी०ओ० I(1)]

New Delhi, the 6th April, 1977

S.O. 1186—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri G. Lakshminarayana as the Managing Director of Indian Bank for a further period commencing on 1st April, 1977 and ending with 30th April, 1977.

[No. F. 9/3/77-BO I(1)]

कां०अ० 1187—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री जी० लक्ष्मीनारायण को, दिनांक 1 अप्रैल, 1977 से इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से इंडियन बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/3/77-बी०ओ० I(2)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 1187—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri G. Lakshminarayana, who has been re-appointed as Managing Director of Indian Bank with effect from 1st April, 1977, to be the Chairman of the Board of Directors of Indian Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/3/77-BO I(2)]

BALDEV SINGH Dy. Secy

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा पक्ष)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1977

कां०अ० 1188—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की प्राग 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा नियम 1939 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त प्राग की प्राधान्य (1) में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का विनिर्दिष्ट रूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राग पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2 ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि में पूर्ण नियमों के उक्त प्राग की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्राग

1 इन नियमों का नाम बीमा (संशोधन) नियम, 1977 है।

2 बीमा नियम, 1939 में, नियम 17 डी में अतः से आने वाले स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

[सं० 102-आई०एफ (1)/69-51 (3)-बीमा 1/76]

आर० डी० खानवालकर, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Wing)

New Delhi, the 1st April, 1977

S.O. 1188—The following draft further to amend the Insurance Rules, 1939, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), is published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration by the Central Government after the expiry of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT

1. These rules may be called the Insurance (Amendment) Rules, 1977.

2. In the Insurance Rules, 1939, in rule 17E, the Explanation occurring at the end shall be omitted.

[No. 102-IF(1)/69-51(3)-Ins. I/76]

R. D. KHANWALKAR, Under Secy.

(राजस्व रुकें)

सकाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, कानपुर

कानपुर, 5 अप्रैल, 1977

क्रा० प्रा० 1189 —भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिवृत्ति नं० 21/76 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 21-2-76 के अधीन निर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनियम, 1944 के नियम 232-ए के अनुपालन में निम्नलिखित कौटि के व्यक्तियों के नाम और पते और अन्य विवरण जो कि उपाबद्ध शर्तियों में हैं, प्रकाशित किए जाते हैं :—

(क) वे व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 9 के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए (कनविकटेड) हैं; और

(ख) वे व्यक्ति जिन्हें अधिनियम की धारा 33 में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला पाया गया है और उनपर ऐसे अधिकारी द्वारा, दस हजार रुपये या उससे अधिक की राशि अधिरोपित की गई है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम और नियमावली, 1944 के अधीन दंडित अपराधियों के नामों को दंडित करने वाली शर्तियों विभागीय कार्रवाई में जित अपराधियों पर 10,000 रु० या अधिक का जुर्माना किया गया उनका विवरण

क्रम सं०	नाम और पता	अधिनियम के उपबंध या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम जिसका उल्लंघन किया गया है	अधिरोपित शक्ति की धराराणि	उत्पाद शुल्क या अन्य सम्पत्ति का मूल्य जिसका समय हरण, न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 10 के अधीन किया जाता है या धारा 33 में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा न्याय निर्णीत किए जाने पर जिसका प्राधिकरण किया जाता है	योग्य अधिनियम की धारा 34 के अधीन प्राधिकरण के बदले जुर्माने की धराराणि	नियम 181 के अन्तर्गत का विवरण
1	2	2क	2ख	2ग	2घ	3
1	अथर्टन बेस्ट एंड कंपनी लिमिटेड, कानपुर	173-जी, 9(1) 52ए, 173 एफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	रु० 75,000	—	—	—

न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराए गए (कनविकटेड) अपराधियों का विवरण

—कुछ नहीं—

[अधिसूचना सं० 4/77/सी० सं० 5(30) एम पी/मिम०/एंड जे०/20/76/15459]

कु० श्री० दिव्यप्रसिद्धजी, समाहर्ता

(Revenue Wing)

Office of the Collector of Central Excise, Kanpur

Kanpur, the 5th April, 1977

S.O. 1189.—In pursuance of Rule 232-A of the Central Excise Rules, 1944 issued under Government of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue and Banking), Notification No. 21/76-CE dated 21-2-76, the names and addresses and other particulars of the following categories of persons are published herewith in the table annexed below :—

(a) persons who have been convicted by a Court under Section 9 of the Central Excises & Salt Act, 1944; and

(b) persons who have been found by an officer referred to in Section 33 of the Act to have contravened any of the provisions of the Act or Rules made therein and on whom a penalty of ten thousand rupees or more has been imposed by such officer.

Printed and published under Central Excises & Salt Act & Rules 1944 for Publication
Particulars of offenders on whom a penalty of Rs. 10,000 or more has been imposed in departmental proceedings.

S. No.	Name and Addresses	The provisions of the Act or rule made thereunder contravened	The amount of penalty imposed	The value of excisable goods or other property ordered to be forfeited by a court under Section 10 of the Act or Adjudged by the officer referred to in section 33 to be confiscated	Amount of fine in lieu of confiscation if any imposed under Section 34 of the Act	Particulars of any licence revoked under rule 181
1	2	2(a)	2(b)	2(c)	2(d)	3
1.	Atherton West & Co. Ltd., Kanpur. (F. No. M.P./Adj/10/76)	173-G, 9(1) & 52-A, 173-F of Central Excise Rules, 1944	Rs. 75,000	—	—	—

Particulars of offenders convicted by court of law
-Nil-

[Notification No. 4/77/C. No. V(30) MP/Misc./Adj/20/76/15459
K. SRI. DII IPSINGHJI, Collector

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमाहर्तलिय अहमदाबाद

अहमदाबाद, 5 फरवरी, 1977

सीमा शुल्क

कां०आ० 1190--सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के साथ पठित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 79 सीमा-शुल्क, भिसिल सं० 473/2/75-सीमा शुल्क-हिनाक 18-7-1975, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डी० एन० मेहता, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, अहमदाबाद, गुजरात राज्य के 'अहमदाबाद शहर' (म्युनिसिपल हद) का एतद्वारा भाडागार स्थान (वेयर हाउसिंग स्टेशन) होने की घोषणा करना हूँ।

[सं० 2/77-सीमा शुल्क, भि० सं० VIII/40-21/सी०शु०/76]

डी० एन० मेहता, समाहर्ता

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, AHMEDABAD

Ahmedabad, the 5th February, 1977

CUSTOMS

SO. 1190.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with the Notification No. 79-Cus, F No 473/2/75-Cus VII dated 18-7-75 issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance), New Delhi, I, D. N. Mehta, Collector of Customs & Central Excise, Ahmedabad, hereby declare 'AHMEDABAD CITY' (Municipal Limits), in the State of Gujarat, to be a warehousing station under the said Act.

[No. 2/77-Cus, F No VIII/40-21/Cus/76]

D N MEHTA, Collector

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 5 मार्च 1977

कां०आ० 1191—केन्द्रीय सरकार, सरकार के स्थान (अप्राधिकृत अधिसूचनाओं की वेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री नरेण चन्द्र

13 GI/77-2

मुखर्जी, संपदा प्रबंधक, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, को सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पक्ष के समतुल्य अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और धारा निदेश करती है कि उक्त अधिकारी हमें नीचे ब्रिनिटिड सरकारी स्थानों के प्रयोगों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा —

सरकारी स्थानों के प्रयोग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान, नीचे वर्णित सीमा में स्थित हैं, अर्थात् —

पश्चिमी बंगाल में बर्दवान जिला .

बर्नपुर

(पुलिस थाना हीरापुर के अधीन, मौजे)

याता, नर्मगबन्ध, हीरापुर नबबन्दी, कावाप्रिया, धेनुआ, छाटे-दिशर्हा, बड़ीदिशर्हा मरमरा, लक्ष्मी, कमलपुर, पम्सोहोला, छप्राद ।

(पुलिस थाना कुल्डी के अधीन मौजे)

हेरलगांविया, बेजिरी, अल्बिही बमन्दिहा, निग्रामतापुर, राधानगर, महन्ती, मादेपुर, जमायदाह, नारायणचक, बोन्दी, श्रीपुर, बर्दिकर ।

(पुलिस थाना ग्रामनसोल के अधीन मौजे)

बनेरिया, नर्मगुवा, गोपालपुर, कुमारपुर, गरुई ।

कुल्डी

(पुलिस थाना कुल्डी के अधीन मौजे)

कुल्डी, केन्दुआ, रायदीह (चक्षिंजा सहित), महनादीह मन्वेरिया, कुल्दीह, कुल्दोरा, देवी, पतुरी, पेटियाला पानवाजार, गगुटिया बरकर, इन्कटरा बन्टोरिया

रामनगर

(पुलिस थाना कुल्डी के अधीन मौजे)

(क) रामनगर

(ख) बजौंग, बर्मुंगी (बिहार में जिला बनबाद के पुलिस थाना निर्मा के अधीन मौजे)

2 हुम्नो (पश्चिमी बंगाल में हुगली जिले के पुलिस थाना पण्डुआ के अधीन मौजे)

कुल्डी, पचपरा धमरीन, पण्डुआ, खप्रायन ।

3 बिहार में जिला धनबाद

जमाना—(पुलिस थाना सूरिया के अधीन मौजे) जमाना, पपरकेंद्र, हेल्केन्द्र, पारमबनिया, जन्दाबाद।

नूनीदीह—जीतपुर कोलियरी और बिहार रज्जुमार्ग अधिष्ठाता

(पुलिस थाना सूरिया के अधीन मौजे) नूनीदीह कोलियरी (नूनीदीह), जीतपुर कोलियरी

रज्जुमार्ग—जोरपुखर, महलबनी, स्वर्दीह, पथरदिही, सूदामदीह, टमरा, रोहराबन्ध, डोमगढ़, गिन्दी, छानाता, आसनबनी, काशीपुर, बीरगंजपुर, घरबड़, बरिसाल, या मन्दिमान, गिबपुर खरीकाबा, नियामतपुर।

(पुलिस थाना निर्मा के अधीन मौजे)

सन्तुनिया, बलायचक, पबायन, अकदुरा, टेदुलिया, कांजीदीह, कुधमदहा, भुरसा, दुमरिया, डबरी, मुकुन्ददी, बायी, उर्मा, गुल्यर्दी, लेखरिया, सीतोलपुर, तल्बेरिया, बेलगंजिया, पदमपुरी, लुचिछाबाद, गन्त मरा, अममुराबाग, चोच, जाजतपुर, दुमारकोदा।

4. बिहार में जिला सिधभूम

चिरिया, गुआ, बेवा, अकूआ, आरक्षित वन, निम्ना लोर, बयबेर, दुह्या, घटकुडी, वन, पन्सिरा, बुरु पहाडी, मनोहरपुर, ममर, जिला सिधभूम में इन्ड्रूम फास्केट।

[सं० जी-4 3015/2/75-इण्ड० II]

ए० एन० राजगोपालन, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 8th March, 1977

S.O. 1191.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Naresh Chandra Mukherjee, Estate Manager, Indian Iron and Steel Company Limited, being an officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of Government, to be Estate Officer for the purpose of the said Act and further directs that the said officer shall exercise all the powers conferred and perform all the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified hereunder :—

CATEGORIES OF PUBLIC PREMISES AND LOCAL LIMITS OF JURISDICTION

Premises belonging to or taken on lease by and under the administrative control of, Indian Iron and Steel Company Limited, situated at mouzas mentioned below, namely :—

BURDWAN DISTRICT IN WEST BENGAL

BURNPUR

(Mouzas under Hirapur P.S.)

Santa, Narsingbandh, Hirapur, Nabaghandi, Kalajharia, Dhenua, Chhotodighai, Baradighai, Sanrmaia, Lakasata, Kamalpur, Patmohona, Chaprad.

(Mouzas under Kulti P.S.)

Heralgoria, Bejdih, Aldih, Bamandiha, Niamatpur, Radhanagar, Mahutadi, Sodepur, Jasaidih, Narayanachak, Bokli, Sripur, Badirchak.

(Mouzas under Asansol P.S.)

Bartoria, Narsamuda, Gopalpur, Kumarpur, Garui.

KULTI

(Mouzas under Kulti P.S.)

Kulti, Kendua, Raidih (with Chakpinja), Mahatadih, Manberia, Kuldih, Kultora, Dedi, Punni Petana, Lalbazar, Gangutia, Barakar, Indkata, Baltoria.

RAMNAGAR

(Mouzas under Kulti P.S.)

(a) Ramnagar.

(b) Barjora, Barmuri (Mouzas under Nirsia P. S. District Dhanbad in Bihar.)

2. HOOGHLY.

(Mouzas under Pandua P.S. District Hooghly in West Bengal)

Multi, Panchpara, Dhamasin, Pandua, Khannayan

3. Dhanbad District in Bihar.

Chasnalla

(Mouzas under Jharia P. S.)

Chasnalla, Upperkendra, Hetkendra, Parasbanja, Chandrabad.

NOONODIH

JITPUR COLLIERY AND BIHAR ROPEWAY INSTALLATIONS

(Mouzas under Jharia P.S.)

NOONODIH COLLIERIES (Nunikdih), JITPUR COLLIERY

Ropeways :—Jorupukhar, Mahulbani, Swardih, Pathardihi, Sudamdih, Tasra, Rohrabandh, Domgarh, Sirdi, Chhatatanr, Asanbani, Kalipur, Birsinghpur, Gharbar, Barisal or Salbisal, Sheopur, Kharikabad, Neamatpur.

(Mouzas under Nirsia P.S.)

Susunliya, Balaichak, Pabayan, Ankadura, Tentulya, Kanjidihi, Kushundaha, Bhurua, Dumarya, Dhabari, Makunddi, Barya, Urmia, Gulardi, Iedaharia, Sonolapur, Talberia, Benagaria, Patlabari, Luchibad, Shanimaia, Amlamurabag, Chanch, Jajatur, Dumarkonda.

4. SINGHBHUM DISTRICT IN BIHAR

Chiria, Gua, Bewa, Ankua Reserve Forest, Timra, Lor, Baiberu, Duia, Ghatkuri forest, Pansira Buru Hills, Monoharpur, Mamar. Dhalbhoom Phosphate in District Singhbhum.

[No. G-43015/2/75-Ind. II]

A. N. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1977

का०आ० 1192—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 1(3) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी० पी० मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी, वस्त्र विभाग को, श्री मणिनारायणस्वामी के स्थान पर, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में पद द्वारा मनोनीत करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 642 दिनांक 16 फरवरी, 1977 में निम्नोक्त और मणोधन करती है, अर्थात्,

उक्त अधिनियम में, क्रमांक 27 पर दी गई प्रविष्टि के लिए निम्नोक्त प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् —

“27 श्री पी० पी० सिंगला, विशेष कार्य अधिकारी, वस्त्र विभाग, नई दिल्ली।”

[फा० सं० 25012 (21)/76-रशम]

एस० वेंगुगोपालन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of textiles)

New Delhi, 6th April, 1977

S.O. 1192.—In exercise of the powers conferred by Section 4(3)(b) of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby nominates Shri P. P. Singla, Officer on Special Duty Department of Textiles, as a member of the Central Silk Board vice Shri Mani Narayanswami and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. No. 642 dated the 16th February, 1977, namely,

In the said Notification, for the entry against serial number 27, the following entry shall be substituted, namely :—

“27. Shri P. P. Singla, Officer on Special Duty, Department of Textiles, New Delhi”

[F. N. 25012/24/76-Silk]

S VENUGOPALAN, Director

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1977

फा० आ० 1193.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सदर गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन, सुरत द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास की अग्रिम सविदाओं के बारे में, 16 अप्रैल, 1977 से 15 अप्रैल, 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) को एक वर्ष की अतिरिक्त वात्सविधि के लिए मान्यता प्रदान करने हैं।

2 एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं।

[मिनिस्टर सं० 12(1)—आई० टी०/76]

New Delhi, the 7th April, 1977

S.O. 1193.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Southern Gujarat Cotton Dealers' Association, Surat, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 16th April, 1977 to the 15th April, 1978 (both days inclusive), in respect of Forward Contracts in Cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission

[F. No. 12(3)-IT/76]

फा० आ० 1194.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन बम्बई ओयल सीड्स और ओयल्स एक्सचेंज लि० बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को भूगर्भी का तेल की अग्रिम सविदाओं के बारे में, 25 अप्रैल, 1977 से 24 अप्रैल, 1978 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) को एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करनी है।

2. एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त बम्बई ओयल सीड्स और ओयल्स एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं।

[मिनिस्टर सं० 12(6)—आई० टी०/76]

अ० मुबई, उप सचिव

S.O. 1194.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Bombay Oilseeds & Oils Exchange Ltd, Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said exchange for a further period of one year from the 25th April, 1977 to the 24th April, 1978 (both days inclusive) in respect of forward contracts in groundnut oil.

2 The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(6)-IT/76]

A. MUBAYI, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1977

फा० आ० 1195.—आई० डी० आर० 7/6/77—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1962 के नियम 3, 4 और 8 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव, वस्त्र विभाग को, श्री दी० के० शाह के, श्री पी० पी० मंचल, विशेष कार्य अधिकारी (वस्त्र) को श्री के० रामानुजम के और श्री एस० वेणुगोपालन, निदेशक (वस्त्र) को श्री ए० के० चन्द्र के स्थान पर, मानव-निर्मित वस्त्र विकास परिषद् के सदस्यों के रूप में, 16 जुलाई, 1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित हैं, नियुक्त करनी है, सचिव, वस्त्र-विभाग को उक्त परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने हैं और भारत सरकार

के उच्चाय मन्त्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० का० आ० 2371-आई०डी०आर०ए०/6/2/75 तारीख 17 जुलाई, 1975 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, (i) पैरा 1 में, क्रम संख्या 1, 21 और 23 और उनमें सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. सचिव,
वस्त्र विभाग,
वाणिज्य मन्त्रालय,
नई दिल्ली।"

"21. श्री पी० पी० सिंगला,
विशेष कार्य अधिकारी (वस्त्र),
वस्त्र विभाग,
वाणिज्य मन्त्रालय,
नई दिल्ली।"

"23. श्री एस० वेनुगोपालन,
निदेशक (वस्त्र),
वस्त्र विभाग,
वाणिज्य मन्त्रालय,
नई दिल्ली।"

(ii) पैरा 2 में, "श्री एस० के० चन्द्र, संयुक्त वस्त्र आयुक्त, वस्त्र-आयुक्त कार्यालय, मुम्बई," शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, शब्द और अक्षर "श्री एस० वेनुगोपालन, निदेशक, वस्त्र विभाग," रखे जाएंगे।

[सं० 8/7/74-मो डी एन']

प्रेम नारायण, प्रवर सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRY (Department of Industrial Development)

New Delhi, the 11th April, 1977

ORDER

S.O. 1195.IDRA/6/2/77.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3, 4 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Secretary, Department of Textiles vice Shri V. K. Shah, Shri P. P. Singla, O. S. D. (Textiles) vice Shri K. Ramanujan and Shri S. Venugopalan, Director (Textiles) vice Shri A. K. Chandra, as members of the Development Council for Man-made Textiles for a period upto and inclusive of the 16th July, 1977, appoints the Secretary, Department of Textiles as Chairman of the said Council and makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Industry. Department of Industrial Development No. S. O. 2371/IDRA/6/2/75, dated the 17th July, 1975, namely :—

In the said Order, (i) in paragraph 1, for Serial Nos. 1, 21 and 23 and entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall respectively be substituted, namely:—

"1. Secretary,
Department of Textiles,
Ministry of Commerce,
New Delhi."

"21. Shri P. P. Singla,
Officer on Special Duty (Textiles),
Department of Textiles,
Ministry of Commerce,
New Delhi."

"23. Shri S. Venugopalan,
Director (Textiles),
Department of Textiles,
Ministry of Commerce,
New Delhi."

(ii) in paragraph 2, for the words and letters "Shri A. K. Chandra, Joint Textile Commissioner, Office of the Textile Commissioner, Bombay", the words and letters "Shri S. Venugopalan, Director, Department of Textiles" shall be substituted.

[No. 8/7/74-CDN]

PREM NARAIN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1977

आ०आ० 1196—यतः भारत सरकार, घृतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालय की 30 दिसम्बर, 1960 की अधिसूचना संख्या 17-59/59-एम० 1 में भारत सरकार ने निदेश दिया है कि चिकागो विष्वक्विद्यालय द्वारा प्रदत्त "एम०डी (चिकागो), संयुक्त राज्य अमेरिका" (चिकित्सा अहर्ता भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयाजन के लिए एक मान्यता प्राप्त अहर्ता होंगी ;

और यतः डा० एच० बी० करोबेल जिनके पास उक्त अहर्ता है उन्हें फिलहाल अध्यापन तथा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड ब्राउन मेमोरियल अस्पताल, लुधियाना, पंजाब के साथ सम्बद्ध किया गया है ,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अनुसूच के खंड (ग) के अनुसमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा—

(i) 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि तक, अर्थात्

(ii) उस अवधि के दौरान जिस में डा० एच० बी० करोबेल उक्त क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड ब्राउन मेमोरियल अस्पताल, लुधियाना, के साथ सम्बद्ध है, जो भी कम हो, जिस अवधि के लिए उपयुक्त डॉक्टर की संबंधी प्रैक्टिस सीमित होगी निर्दिष्ट करती है।

[सं० सी०-11016/5/77-एम०पी०डी]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 4th April, 1977

S.O. 1196.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 17-59/59-MI, dated the 30th December, 1960, the Central Government has directed that the Medical qualification, "M.D. (Chicago), U.S.A.", granted by the Chicago University shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Edward B. Crowell, who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, Ludhiana, Punjab, for the purposes of teaching and research;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- (i) a period up to the 31st December, 1977, or
- (ii) the period during which Dr. Edward B. Crowell is attached to the said Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, Ludhiana, whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/5/77-MPT]

कां० प्र० 1197.—यन. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण से निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे लिखे गये विश्वविद्यालय ने उनके आगे लिखी गई तारीख से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित कर लिया है; अर्थात्:—

व्यक्ति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचन की तारीख
डा० पी० लक्ष्मणराव, हृदय रोग विज्ञान के प्रोफेसर, आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम।	आंध्र विश्वविद्यालय	6-10-1976
डा० ए० बी० सगमनेरकर, कालोनी नर्सिंग होम, 209, सदाशिव पेठ, पुना-30	पुना विश्वविद्यालय	15-10-1976
डा० जी० एम० जाधव, मरुस्वर्णी अस्पताल, लक्ष्मीपुरी, कोहलापुर।	शिवाजी विश्वविद्यालय	17-11-1976
डा० एच० सी० वर्मा, प्रिंसिपल तथा डीन, चिकित्सा संकाय, एल० एल० आर० एम० मेडिकल कॉलेज, मेरठ।	मेरठ विश्वविद्यालय	19-1-1977

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी 1960 की अधिसूचना संख्या 5-23/59-एम० I में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्

उक्त अधिनियम में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत क्रम संख्या 8, 18, 32 और 44 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियाँ रख ली जाएँ; अर्थात्

"8. डा० पी० लक्ष्मणराव, हृदय रोग विज्ञान के प्रोफेसर, आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम-2

18. डा० ए० बी० सगमनेरकर, कालोनी नर्सिंग होम, 209, सदाशिव पेठ, पुना-30

32. डा० जी० एम० जाधव, मरुस्वर्णी अस्पताल, लक्ष्मीपुरी, कोहलापुर।

44. डा० एच० सी० वर्मा, प्रिंसिपल, एल० एल० आर० एम० मेडिकल कॉलेज, मेरठ (उत्तर प्रदेश)"

[सं० बी-11013/1/76-एम० पी० टी०]

S. O. 1197. Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the following persons have been elected by the University specified against each of them to be members of the Medical Council of India with effect from the date noted against each, namely:—

Name of the person	Name of the University	Date of election
Dr. P. Lakshmana Rao, Professor of Cardiology, Andhra Medical College, Visakhapatnam.	Andhra University	6-10-1976
Dr. A.V. Sangamnerkar, Colony Nursing Home, 209, Sadashiv Peth, Poona-30.	University of Poona	15-10-1976
Dr. G.M. Jadhav, Saraswati Hospital, Laxmipuri, Kolhapur.	Shivaji University	17-11-1976
Dr. H.C. Verma, Principal and Dean, Faculty of Medicine, L.L.R.M. Medical College, Meerut.	Meerut University	19-1-1977

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 5-23/57-MI, dated the 7th January, 1960, namely;

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial numbers 8, 18, 32 and 44 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

"8. Dr. P. Lakshmana, Rao, Professor of Cardiology, Andhra Medical College, Visakhapatnam-2.

18. Dr. A.V. Sangamnerkar, Colony Nursing Home, 209, Sadashiv Peth, Poona-30.

32. Dr. G.M. Jadhav, Saraswati Hospital, Laxmipuri, Kolhapur.

44. Dr. H.C. Verma, Principal, Faculty of Medicine, L.L.R.M. Medical College Meerut, (U.P.)."

[No. V-11013/1/76-MPT]

का० आ० 1198—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में सरकारी मानसिक रोग अस्पताल, त्रिवेन्द्रम के अधीक्षक डा० मन्कुशी मन्थाकुमार का 8 नवम्बर, 1976 से केरल क्षेत्र से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य चुन लिया गया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-एम० 1 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में “धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्वाचित” शीर्ष के अन्तर्गत क्रमसंख्या 2 और तत्संबन्धी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रख ली जाए ; अर्थात्

“2. डा० मन्कुशी मन्थाकुमार
अधीक्षक
सरकारी मानसिक रोग अस्पताल,
त्रिवेन्द्रम-695005”

[सं० बी-11013/1/76-एम० पी० टी०]

S.O. 1198.—Whereas in pursuance of clause (c) of Sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. Sankunny, Santhakumar, Superintendent, Government Mental Hospital, Trivandrum, has been elected from the Kerala Constituency to be a member of the Medical Council of India, with effect from the 8th November, 1976;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (c) of sub-section (1) of section 3”, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“2. Dr. Sankunny Santhakumar,
Superintendent,
Government Mental Hospital,
Trivandrum-695005.”

[No. V. 11013/1/76-MPT]

का०आ० 1199—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड के (ख) के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे लिखे गये विश्वविद्यालय ने उनके आगे लिखी गई तारीख से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित कर लिया है ; अर्थात्

सदस्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचन की तारीख
डा० एन० के० जगताप, 34, शंकर नगर, नागपुर (महाराष्ट्र)	नागपुर विश्वविद्यालय	16-10-1976
प्रोफेसर पी०के० कार, वी० एम० एम० मेडिकल कालेज, बुरला (उड़ीसा)	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	11-11-1976

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-एम० 1 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात्

उक्त अधिसूचना में “धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्वाचित” शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 16 और 40 तथा तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएँ तथा प्रविष्टियाँ क्रमशः रख ली जाएँ ; अर्थात्

“16. डा० एन० के० जगताप,
34, शंकर नगर, नागपुर
(महाराष्ट्र)

40. प्रोफेसर पी०के० कार,
प्रिंसिपल, वी० एम० एम०
मेडिकल कालेज, बुरला
(उड़ीसा)”

[संख्या बी०-11013/1/76-एम० पी० टी०]

एम० श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 1199.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the following persons have been elected by the University specified against each of India with effect from the date noted against each, namely :—

Name of the member	Name of the University	Date of election
Dr. M.K. Jagtap, 34, Shankar Nagar, Nagpur, Maharashtra.	Nagpur University	16-10-1976
Professor P.K. Kar, Principal, V.S.S. Medical College, Burla, Orissa.	Sambalpur University	11-11-1976

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3”, for serial numbers 16 and 40 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

“16. Dr. M.K. Jagtap,
34, Shankar Nagar,
Nagpur, Maharashtra.

40. Professor P.K. Kar,
Principal,
V.S.S. Medical College,
Burla, Orissa.,

[No. V. 11013/1/76-MPT]

S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

कृषि व सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1977

क्रा० आ० 1200.—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्निकरण) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के खण्ड (च) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्निकरण नियम, 1937 के नियम 4 के खण्ड (झ) और (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, एगमार्क के अर्थात् श्रेणीकृत कच्चा मांस (शीतल/हिमायित) के लिए लेबिल प्रभार प्रति किलोग्राम या उसके भाग पर 25 पैसे की दर से निश्चित करती है।

[सं० 13-9/75-ए० एम०]

आर० एन० बक्षी, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 31st March, 1977

S.O. 1200.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and clauses (i) and (k) of rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the Central Government hereby fixes, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the label charges for raw meat (chilled/frozen) graded under Agmark at the rate of 25 paise per Kg. or part thereof.

[No. 13-9/75-AM]

R. N. BAKSHI, Under Secy.

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1977

क्रा० आ० 1201.—केन्द्रीय सिविल सेवा (श्रेणीकरण), नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 31 के साथ पठित, नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० क्रा०आ० 2054 तारीख, सितम्बर, 1959 की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करने हैं, अर्थात्—

उक्त अनुसूची में, भाग 1 में, "पुरातत्व विभाग" शीर्षक और उसके नीचे उक्त शीर्षक में सवन्वित प्रविष्टियों का खोप किया जाएगा।

[सं० सी० 11011/1/77-विजि० (सी)]

एम० लक्ष्मीनारायण, अवर सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 5th April, 1977

S.O. 1201.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24, read with rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendment in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Scientific Research & Cultural

Affairs No. S.O. 2054, dated the 9th September, 1959, namely:—

In the said Schedule in Part 1, the heading,

"Department of Archaeology" and the entries thereunder relating to the said heading shall be omitted.

[No. C. 11011/1/77-Vig.(C)]

M. LAKSHMINARAYANA, Under Secy.

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1977

(व्यापार पक्ष)

क्रा०आ० 1202.—व्यापार पक्ष अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 90 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पतवद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की तारीख 16 जून, 1964 की अधिसूचना सं० सा० आ० 2227 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में;—

(क) मद सं० (i) के सामने, संक्षेपण, एक और शब्द "प्रत्येक 1.50 रु०" के स्थान पर संक्षेपण एक और शब्द "प्रत्येक 3.00 रु०" रखे जायें,

(ख) मद सं० (ii) के सामने, संक्षेपण एक और शब्द "प्रत्येक 1.00 रु०" के स्थान पर संक्षेपण एक और शब्द "प्रत्येक 2.00 रु०" रखे जायें।

[क्रा० सं० 5-एमएमआर(15)/7-एमएम]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 31st March, 1977

(Merchant Shipping)

S.O. 1202.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 90 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport (Transport Wing) No. S.O. 2227, dated the 16th June, 1964, namely:—

In the said notification,—

(a) against item No. (i), for the abbreviation, figures and word "Rs. 1.00 each", the abbreviation figures and word "Rs. 3.00 each" shall be substituted

(b) against item No. (ii), for the abbreviation, figures and word "Rs. 1.50 each", the abbreviation figures and word "Rs. 2.00 each" shall be substituted.

[F. No. 5-MSR(15)/76-MA]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1977

का० प्रा० 1203.—भारतीय व्यापार पोत (नौविक राजगार कार्यालय, बम्बई) नियम, 1954 के नियम 2 के खण्ड II के अनुसूचना में और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०प्रा० 4835, तारीख 3 दिसम्बर, 1976 को अधिसूचना करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बम्बई में नौवहन महानिदेशक और बम्बई में नौवहन बरिष्ठ उपमहानिदेशक पदेन, को उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए अपील अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा० सं० एम एम ई (42)/76-एम टी]

New Delhi, the 6th April, 1977

S.O. 1203.—In pursuance of clause (i) of rule 2 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Officer, Bombay) Rules, 1954, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 4835 dated 3rd December, 1976, the Central Government hereby appoints the Director General of Shipping, Bombay and the Senior Deputy Director General of Shipping, Bombay ex-officio, as the Appellate Authorities for the purposes of the said rules.

[File No. MSE(42)/76-MT]

का० प्रा० 1204.—भारतीय व्यापार पोत (नौविक राजगार कार्यालय, कलकत्ता) नियम, 1954 के नियम 2 के खण्ड II के अनुसूचना में और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०प्रा० 4834, तारीख 3 दिसम्बर, 1976 को अधिसूचना करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बम्बई में नौवहन महानिदेशक और बम्बई में नौवहन बरिष्ठ उपमहानिदेशक पदेन, को उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए अपील अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा० सं० एम एम ई (42)/76-एम टी]

श्रीमती बी० निर्मल, अवसर सचिव

S.O. 1204.—In pursuance of clause (ii) of rule 2 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 4834, dated the 3rd December, 1976 the Central Government hereby appoints the Director General of Shipping, Bombay and the Senior Deputy Director General of Shipping, Bombay, ex-officio, as the Appellate Authorities for the purposes of the said rules.

[F. No. MSE(42)/76-MT]

Smt B NIRMAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1977

का० प्रा० 1205.—सोटिंगाडी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 42 की उपधारा (3) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० 39-टोएफ़ी/12/70-III, दिनांक 15-5-1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, मख 3 के बाद, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्—

“4 निम्नलिखित व्यक्तियों का स जात जाने व्यक्तियों के वि-
ध्वन होने वाले टैकर, अर्थात्—

- (i) राष्ट्रपति
- (ii) उपराष्ट्रपति
- (iii) प्रधान मंत्री
- (iv) अन्य मंत्री, अर्थात् मंत्री परिषद् के अन्य सदस्य,
चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिनमें
उपमन्त्री भी शामिल है।

(v) विदेशी राज्याध्यक्ष, विदेशी सरकारों के उपराष्ट्रपति

और अध्यक्ष

(vi) सेनाध्यक्ष

(vii) नौसेनाध्यक्ष

(viii) वायुसेना अध्यक्ष

(ix) बरिष्ठ सेना अधिकारी और बरिष्ठ निविलियन
अधिकारी, चिनका रक्षा संगठना में सम्मिलित हो।

टिप्पणी—शब्द “बरिष्ठ सेना अधिकारी” और “बरिष्ठ निविलियन
अधिकारी” से क्रमशः मुख्यालय में सेवारत पुलिस
सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त सचिव तथा उच्चतर स्तर के
निविलियन अधिकारी अभिप्रेत हैं।

[सं० टी० जो० एम० (46)/76]

एन० ए० ए० नारायणन, उप सचिव

New Delhi, the 13th April, 1977

S.O. 1205.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (3) of section 42 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. 39-TAG/(12)/70, III dated the 15th May, 1973, namely:—

In the said notification, after item 3, the following shall be inserted namely:—

“4. Tankers carrying fuel for aircrafts carrying the following persons, namely. —

- (i) President.
- (ii) Vice President.
- (iii) Prime Minister
- (iv) Other Ministers that is to say, other members of the Council of Ministers, by whatever name called, including, Deputy Ministers.
- (v) Foreign heads of States, Vice Presidents and heads of Foreign Governments.
- (vi) Chief of the Army Staff
- (vii) Chief of the Naval Staff
- (viii) Chief of the Air Staff
- (ix) Senior service officers and senior civilian officers who are connected with Defence Organisations.

Note:—The terms “senior service Officers” and “senior civilian officers” mean Police Security Officers at service Headquarters and civilian officers of the rank of Joint Secretary and above respectively.”

[No. TGM (46)/76]

N. A. A NARAYANAN, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1977

का० प्रा० 1206.—इस मंत्रालय की दिनांक 22-12-76 की अधिसूचना संख्या के 12016(1)/76-भाग-II में निम्नलिखित शब्दों की जाती है जिन्हें दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) में एम० प्रा० सं० 209 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

- (1) योजना मन्त्रालय की के आगे लिखे आकड़ा 6,963 के स्थान पर 6,940 पड़ा जाए।
- (2) “प्रस्तावित 1981 जनसंख्या” कालम के अन्तर्गत जोड़ के आगे दिखाए गए आकड़ा 52,62,800 के स्थान पर 52,62,940 पड़ा जाए।

[ग० के० 12016(1)/77 सं० टी०-]

टी० पी० मोहंती अवसर सचिव

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 14th April, 1977

New Delhi, the 31st March, 1977

S.O. 1206.—The following corrections are carried out in this Ministry's Notification No. K-12016(1)/76-Pt. II, dated 22-12-76 which appeared under S.O. No. 209 in the Gazette of India Part II, Section 3—Sub-Section (ii), dated the 15th January 1977:—

- (i) The figure 6,963 appearing against Planning Divisions D—New Delhi may be read as 6,930.
- (ii) The figure 52,62,800 shown against total under column "Proposed 1981 population" may be read as 52,62,940.

[No. K-12016(1)/72-UDI]
D. P. OHRI, Under Secy.

संसार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1977

क्र० आ० 1207.—स्वायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पेरियनायकन पायलम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-77 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-15/77 पी० एन० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 13th April, 1977

S.O. 1207.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1977 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Perlanaickenpalayam Telephone Exchange, Coimbatore District.

[No. 5-15/77-PHB]

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1977

क्र० आ० 1208.—क्र०आ० संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बदायुं टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-77 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/77-पी०एच०बी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी०)

S.O. 1208.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. 627 dated the 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1977 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Budaun Telephone Exchange, U. P. Circle.

[No. 5-11/77-PHB.]

P. C. GUPTA, Asst. Director General (PHB)

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1977

क्र० आ० 1209.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व बोर्ड में भूमि सुधार आयुक्त को भूमि सुधार आयुक्त के रूप में सौंपे गए कार्यों के प्रभावित उक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत संबन्धित आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 1(4)/विशेष सेल/77-एस० एस०-II]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 5th April, 1977

S.O. 1209.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Land Reforms Commissioner, Board of Revenue, Government of Uttar Pradesh, as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his duties as Land Reforms Commissioner, the functions assigned to him as Settlement Commissioner by or under the aforesaid Act.

[No. 1(4)/Spl. Cell/77-SS II]

क्र० आ० 1210.—निष्कात सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में आयुक्त एवं सचिव को उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत उप महाअभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए उप महाअभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1(4)/विशेष सेल/77-एस० एस०-II]

S.O. 1210.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints the commissioner-cum-Secretary in the Revenue Department, Government of Uttar Pradesh, as Deputy Custodian General for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian General by or under the said Act.

[No. 1(4)/Spl. Cell/77-SS.II]

क्र० आ० 1211.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली

शक्तियों का, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में आयुक्त-व-सचिव द्वारा, अपने कार्यों के अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रावृत्त प्ल की भूमियों और परिसम्पत्तियों के सम्बंध में प्रयोग किया जा सकेगा।

[संख्या 1(4)/विशेष सेल/77-एस० एस-II]

दीनानाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

S.O. 1211.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that any powers exercisable by it under Section 33 of the said Act shall be exercisable also by the Commissioner-cum-Secretary in the Revenue Department of the Government of Uttar Pradesh, in addition to his own duties, in respect of the lands and properties forming part of the Compensation Pool within the State of Uttar Pradesh.

[No. 1(4)/Spl. Cell/77-SS. II]

D. N. ASIJA, Jt. Director

क्रा० आ० 1212.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य बंदोबस्त आयुक्त भूमि-सुधार आयुक्त, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्हें इस विभाग की दिनांक 5 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या 1(4)/विशेष सेल/77-एस० एस-II द्वारा बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, को निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपते हैं :—

- (1) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अपील को सुनने की शक्तियाँ।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत पुनरीक्षणों को सुनने की शक्तियाँ।
- (3) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत मामलों को हस्तांतरित करने की शक्तियाँ।

[संख्या 1(4)/विशेष सेल/77-एस० एस-II]

कुसुम प्रसाद, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त

S.O. 1212.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (Act No. 44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Land Reforms Commissioner, Board of Revenue, Government of Uttar Pradesh, appointed as Settlement Commissioner, vide this Department's notification No. 1(4)/Spl. Cell/77/SS-II, dated 5th April, 1977,

The following powers :—

- (i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said Act.
- (ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.
- (iii) Powers to transfer cases under Section 28 of the said Act.

[No. 1(4)/Spl. Cell/77/SS. II]

KUSUM PRASAD, Chief Settlement Commissioner

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1977

क्रा० आ० 1213—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उप धारा (3) द्वारा मुझे महा अधिरक्षक के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अशोक चन्द्र बाबुयोपाध्याय, आयुक्त-व-सचिव, राजस्व, विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्हें इस विभाग की दिनांक 5 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या 1(4)/विशेष सेल/77-एस० एस-II द्वारा उप महा अधिरक्षक के रूप में

नियुक्त किया गया है, को महा अधिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपता हूँ :—

- (1) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अपीलें सुनने की शक्तियाँ, और
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्तियाँ—

[संख्या 1(4)/विशेषसेल/77-एस० एस-II]

अशोक चन्द्र बाबुयोपाध्याय, महा अधिरक्षक

New Delhi, the 6th April, 1977

S.O. 1213.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by Sub-Section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I, A. C. Bandyopadhyay, hereby delegate to the Commissioner and Secretary, Revenue Department, Government of Uttar Pradesh, appointed as Deputy Custodian General vide this Department's notification No. 1(4)/Spl. Cell/SS-II, dated the 5th April, 1977,

the following powers of the Custodian General :—

- (i) Powers under Section 24 of the said Act to hear appeals ; and
- (ii) Powers of revision under Section 27 of the said Act.

[No. 1(4)/Spl. Cell/77/SS. II]

A. C. BANDYOPADHYAY, Custodian General

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1977

क्रा० आ० 1214.—केन्द्रीय सरकार, अन्नक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अन्नक खान श्रम कल्याण निधि से वित्त-पोषित क्रियाकलापों की निम्नलिखित रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा विवरण और उक्त निधि के 1976-77 वर्ष की प्रारम्भिक और वर्षों के प्राक्कलन के साथ प्रकाशित करती है।

भाग-1

1. साधारण अन्नक खान श्रम कल्याण निधि का गठन अन्नक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) के अधीन अन्नक खान उद्योगों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण से संबंधित स्कीमों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

2. अधिनियम में, निर्यात की गई सभी अन्नक पर मूल्यानुसार 6½ प्रतिशत की अधिकतम दर पर सीमानुसूक्त के उपग्रहण के लिए उपबंध किया गया है। उपरर की दर, जो कि पड़ते मूल्यानुसार 2½ थी, 15 जुलाई, 1974 से 3½ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। संग्रहणों का आबंटन विभिन्न अन्नक उत्पादन क्षेत्रों में उनके औसत उत्पादन के अनुपात में कल्याणकारी उपायों से संबंधित व्यय के लिए किया जाना है।

भाग-2

सुविधाओं की व्यवस्था

(क) विकिसकीय :

अन्नक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा अन्नक कर्मचारों और उनके आश्रितों के लिए उचित रूप से व्यापक विकिसकीय सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उनके अन्तर्गत अस्पतालों, प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्रों की व्यवस्था और उनका बनाए रखना, गृहोपचार सहित क्षयरोग

के उपचार की सुविधाएं, आयुर्वेदिक औषधालयों सहित औषधालय सेवाएं और अन्य सुविधाएं आदि भी हैं, रिपोर्टों से संबंधित वर्ष के दौरान अन्नक खानकों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए कल्याण संगठन द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय और प्रादेशिक अस्पतालों कोपित किए जाते रहे :-

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	गणना की संख्या
1	केन्द्रीय अस्पताल, करमा (बिहार)	100
2	केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर (राजस्थान)	30
3	केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेड़ू (आन्ध्र प्रदेश)	40
4	प्रादेशिक अस्पताल, तिसरी (बिहार)	30
5	प्रादेशिक अस्पताल, तालपुर (आन्ध्र प्रदेश)	10
6	क्षयरोग अस्पताल, करमा (बिहार)	50
7	केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेड़ू से सलग्न क्षयरोग बार्ड, (आन्ध्र प्रदेश)	20
8	ग्रामली और बागौर (राजस्थान के अन्नक औषधालयों में अन्नरग बार्ड)	5 प्रत्येक में
9	प्रादेशिक अस्पताल, सईदापुरम (अनाहरी बार्ड)	10

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य चिकित्सा संस्थाएं भी इन तीन अन्नक उत्पादक राज्यों में कार्य करती रही :-

चिकित्सकीय संस्थाएं	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
आयुर्वेदिक औषधालय	3	8	9	19
एलोपैथिक औषधालय	1	5	—	6
चलचिकित्सा यूनिट	1	3	1	5
प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र	4	—	3	7
लघु सामुदायिक केन्द्र	—	5	—	5

कल्याण संगठन खानकों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करता रहा है। क्षयरोग अस्पताल और क्लिनिक स्थापित करने के अलावा सरकारी क्षयरोग और छाती रोग अस्पताल नैलोर में छह गणना पूर्णतया अन्नक खानकों और उनके कुटुम्ब के उपयोग के लिए आरक्षित रही। राजस्थान प्रदेश में 4 ग्रामाएं क्षयरोग आरोग्य निवास मंदार-अजमेर में आरक्षित की गई है। सईदापुरम (आन्ध्र प्रदेश) के एक अन्नक औषधालय को अनाहरी क्षयरोग अस्पताल में परिवर्तित किए जाने का आदेश किया जा चुका है और 27-12-1975 से क्षयरोग की आवासीय चिकित्सा कार्यान्वित की गई है। उन अन्नक खानकों के जिनका उपचार कल्याण संगठन द्वारा स्थापित क्षयरोग अस्पतालों में हो, आश्रितों को, ऐसे मामलों में जहां कुटुम्ब में कोई उपार्जक सदस्य नहीं, छह मास की अवधि के लिए या इस समय तक जबकि क्षमिक पुनः रोजगार प्राप्त करता है, जो भी पूर्वपर हो, 50 रुपए प्रतिमास निर्वाह भत्ता दिया जाता है।

विविध चिकित्सकीय सुविधाएं

नेतृत्वारी कुष्ठरोग अस्पताल में बिहार के उन अन्नक खानकों के, जो कुष्ठ से पीड़ित हैं, उपचार की व्यवस्था जारी रखी गई। कयर से पीड़ित अन्नक खानकों के उपचार के लिए कल-अस्पताल, ग्रामनसोंग में और मानसिक रोगों के लिए मानसिक रोग अस्पताल, रांची में व्यवस्था जारी रखी गई।

एक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो भवन और उसके परिवेश के निरीक्षण और आन्ध्र प्रदेश में कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उपबन्ध करता है, आरम्भ किया गया है। अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं निम्नलिखित हैं:-

1. क्षयरोग पीड़ित अन्नक खानकों के लिए आवासीय चिकित्सा स्कीम 27-12-1975 से आरम्भ की गई है।

2. अन्नक खानकों को टेलेन से उन्मुक्त करने का कार्य सम्बद्ध खान प्रबन्धों एवं महानिदेशक, खान सुरक्षा के सहयोग से आरम्भ किया गया है।

3. 16-2-1976 से पहली बार चलनशील कार्यवाहक महिला चिकित्सक उटुशुर, सईदापुरम, तालपुर स्थित अस्पतालों में जन्मपूर्व, जन्म पश्चात् देखभाल तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि की देख-रेख के लिए जाने लगी है।

4. आन्ध्र प्रदेश के अन्नक खान क्षेत्र में पहली बार मुख्यतः अन्नक खानों के लाभ के लिए मुक्तचक्षु शिबिर चलाया गया। इसका उद्घाटन भारत सरकार के श्रम मंत्री ने किया। यह भी समझा जाता है कि भारत सरकार के अधीन कल्याण संगठनों में यह अपनी तरह का पहला शिबिर है। यह शिबिर पूर्ण सफल रहा।

5. एक अन्नक कर्मकार को घातक बुधटना प्रसुविधाएं स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं स्वीकृत की गईं।

6. क्षयरोग अस्पताल, नैलोर के अधीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय अस्पताल कालीचेड़ू और प्रादेशिक अस्पताल, तालपुर के यक्षमा निर्वाह रागी और अन्य रोगियों के भोजन को और अधिक पोषक बनाने के लिए पुनरीक्षित किया गया है।

7. यक्षमा निर्वाह भत्ता स्कीम के अधीन 19 आवेदकों को निर्वाह भत्ते स्वीकृत किए गए।

8. इस संगठन द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को किए गए विशेष अनुरोध पर अधीक्षक, डब्ल्यू.एफ.टी. बी० और सी०डी० अस्पताल, नैलोर मार्च, 1976 को केन्द्रीय अस्पताल कालीचेड़ू और अन्य तीन प्रादेशिक अस्पतालों और औषधालयों में क्षयरोग बार्ड के क्षयरोगियों की चिकित्सा और आवासीय चिकित्सा करने वाले रोगियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में भी विनिष्ठ मार्गदर्शन करने के लिए जाने लगे हैं।

9. भारत सरकार ने इस खान क्षेत्र में परिवार नियोजन के संवर्द्धन के लिए आई०एल०ओ० के अधीन केन्द्रों में एक केन्द्र के रूप में केन्द्रीय अस्पताल कालीचेड़ू को चुना है।

(ख) शैक्षिक और आमोद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं

कल्याण संगठन अन्नक कर्मकारों और उनके आश्रितों के लिए शैक्षिक आमोद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बहुउद्देशीय मंथान जिन में प्रत्येक में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और एक नारी कल्याण केन्द्र है चला रहा है। प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों के प्रसार के लिए

कल्याण संगठन के पोषक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी खोले हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार है :—

संस्थाएं	ग्राम्य प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
(क) बहुउद्देशीय संस्थान (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और नारी कल्याण केन्द्र सहित)	—	9*	—	9
(ख) सामुदायिक केन्द्र	1	6	—	7
(ग) नारी निकेतन	—	—	4	4
(घ) प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालय	6	3	—	9
(ङ) पोषक केन्द्र	—	1	—	1
(च) मिश्रित/उच्च विद्यालय	2	4	—	6
(छ) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	—	9	7	16
(ज) खनिकों के बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउस/अस्पताल	2	4	1	7
(झ) चनसिनेमा यूनितें	1	3	1	5
(ञ) अन्नक खनन क्षेत्रों में लगाए गए रेडियो सैट	39	16	—	55
(ट) आनंद-प्रमोद सम्बन्धी क्लब	12	—	9	21
(ठ) भजन मण्डलियां	9	—	13	22
(ड) पुस्तकालय और वाचनालय	—	—	9	9

* बहुउद्देशीय संस्थानों और सामुदायिक केन्द्रों से संलग्न/एम०ई० विद्यालय, करमा के मित्राग्र बिहार प्रदेश के सभी विद्यालय राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे।

(i) अन्नक खनिकों को दी गई कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं का स्वरूप एक जैसा नहीं है। बिहार के बहुउद्देशीय संस्थानों में जिनमें प्रत्येक में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और एक नारी कल्याण केन्द्र है कर्मचारियों को शैक्षिक और आनंद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं। इन केन्द्रों में आने वाली महिलाओं को मिलानाई और बुनाई जैसी वस्तुकारी में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक संस्था प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में काम करती है। नारी कल्याण केन्द्रों में महिला कर्मकार वर्जिंगिरी और मिलानाई; कढ़ाई और नेस कार्य आदि का काम सीखती हैं।

बिहार में मण्डलों के मुख्यालयों में कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :—

- (1) खनिकों के बच्चों को नहलाना।
- (2) प्रौढ़ शिक्षा (पुरुष और महिला दोनों के लिए)।
- (3) गृह शिक्षकीय कक्षाएं।
- (4) अन्नरंग खेलकूद जैसे केरम बोर्ड, शतरंज, लूडो आदि।
- (5) बहिरंग खेलकूद जैसे वालीबाल, कबड्डी, रस्माकशी आदि।
- (6) समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकालय पुस्तक आदि से युक्त अध्ययन कक्ष।

उपकेन्द्रों के कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं :—

- (1) प्रौढ़ शिक्षा (केवल पुरुषों के लिए)।
- (2) गृहशिक्षकीय कक्षाएं (केवल बालकों के लिए)।

(3) अन्नरंग खेलकूद।

(4) समाचार पत्र आदि।

ग्राम्य प्रदेश में, कल्याण संगठन, महिला सामुदायिक केन्द्रों, आनंद-प्रमोद क्लबों, आदि के सुविधाओं की व्यवस्था करता है। सामुदायिक केन्द्रों में महिलाओं को दर्जिगिरी/कशीशकारी लेस सम्बन्धी कार्य आदि सिखनाया जाता है। इन केन्द्रों के काम का पर्यवेक्षण क्रमशः, सहायक भ्रम निरीक्षक और कनिष्ठ सहायक भ्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा किया जाता है।

(ii) ग्राम्य प्रदेश में इस निधि से खर्चा जा रहे सभी विद्यालयों में बच्चों को मुक्त मध्याह्न भोजन, दूध, पुस्तकें, स्लेट, धोले, चप्पलें और वर्डों दी जाती हैं। बिहार में बहुउद्देशीय संस्थानों और सामुदायिक केन्द्रों में आने वाले खनिकों के बच्चों के लिए दूध और टिफिन (पकाये गए राजन में भिज) की व्यवस्था है। राजस्थान में अन्नक खनिकों के स्कूल आने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन, पुस्तकें और स्लेट तथा अन्य लेखन सामग्री दी जाती है।

(iii) अन्नक कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से दूर उच्च विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों के फायदे के लिए कल्याण संगठन ने बोर्डिंग हाउस छात्रावास स्थापित किए हैं।

(iv) अन्नक खनिकों के विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को उनकी मातारण तथा तकनीकी शिक्षा पूरी करने के लिए 10.00 रु० से 75.00 रु० प्रतिमास तक की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। बिहार में अन्नक खनिकों को विद्यालय आने वाले बच्चों को ट्यूशन फीस भी दी जाती है।

(v) कल्याण संगठन की चन सिनेमा यूनितें द्वारा अन्नक खनन क्षेत्रों में पूरे वर्ष सिनेमा गो दिखाए जाते हैं। ये हर स्थान पर बड़ी भीड़ आकृष्ट करते हैं और अन्नक कर्मचारियों में बहुत लोकप्रिय है।

(vi) प्रत्येक वर्ष सभी अन्नक क्षेत्रों में त्रीड़ा और खेलकूद का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को इनाम दिए जाते हैं।

(vii) भ्रम एवं अध्ययन दोनों के लिए सुविधाएं भी दी जाती हैं। राजस्थान प्रदेश के खनिकों के लिए रिपोर्ट के अधीन आने वाली भ्रमि के दौरान एक भारत वर्षीय पर्यटन की व्यवस्था की गई।

(viii) एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर जाने तथा कर्मचारियों का मनोरंजन करने के लिए कीर्तन और भजन मण्डलियों का प्रबन्ध किया जाता है।

(ix) इस निधि से खर्चा जा रहे सभी बहुउद्देशीय संस्थानों/कल्याण केन्द्रों पर खनिकों और उनके कुटुम्ब के आनंद-प्रमोद के लिए रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई है।

(ग) पेयजल की सुविधाएं :

अन्नक खनन क्षेत्रों में पेयजल और अन्य प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल प्रदाय का अभाव एक पुरानी समस्या है। खान प्रबन्ध तन्त्रों को लागत के 75 प्रतिशत तक विनीय सहायता, इन में जो भी कम हो, लेकर जलप्रदाय स्कीम शुरू करने के लिए सहमत किया गया है।

(घ) जलपूर्ति :

कालिबेहू में शीर्षकालीन जल के अभाव की समस्या का हल निकालने के उद्देश्य से केन्द्रीय भ्रम मन्त्री श्री के०बी०रघुनाथ, रेल्वे द्वारा एक स्थायी की जलप्रदाय स्कीम 16-4-76 को चलायी गई। इस स्कीम के लिए स्वीकृत लागत व्यय 1.426 लाख रुपये है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से छह बिन्दू सूत्र के अधीन एक दूसरी महत्वपूर्ण जलप्रदाय स्कीम जिसका स्रोत कान्हुलेन् नदी में है, थोड़ीसेल्वा खनिक ग्राम के लिए प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम की लागत 2,77,000 रु० आँकलित की गई है। भारत सरकार ने 65,750 रु० का अर्धदाय स्वीकृत किया है। ऐसा अनुमान किया जाना है कि उक्त जलप्रदाय स्कीम के पूरे हो जाने पर इस क्षेत्र को दीर्घकालीन जलाभाव की समस्या से राहत मिलेगी।

राजस्थान प्रदेश में पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान कोई नया कुआ खूदवाया/नवीकृत नहीं किया गया क्योंकि कुओं में, भारी वर्षा के कारण, जलस्तर पर्याप्त था। बिहार प्रदेश में अन्नक खान कल्याण निधि संगठन ने ठौरकोला में फुटनैया नदी पर बांध बनाने का कार्य जिम्मे लिया, किन्तु यह स्कीम छोड़ देनी पड़ी क्योंकि उस क्षेत्र की विशेष दशाओं और बांध में प्रत्याशित बाढ़ के जमाओं के कारण वह सफल प्रमाणित न हो सकी। बिहार में 74 कुए खूदवाए गए जिनकी लागत निधि के 7,10,000 रु० पड़ी। निधि द्वारा, पिछले ग्रीष्म के दौरान, "न लाभ न हानि" आधार पर विभागीय टुक से पेयजल के प्रवाय की व्यवस्था की गई थी। आन्ध्र प्रदेश में अब तक 26 कुए खूदवाये गये हैं। कानीबेड ग्राम में जलसमस्या को हल करने के लिए 1 426 लाख रुपये की आकलित लागत पर एक स्थायी जल प्रदाय स्कीम मंजूर की गई है। परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एक और कुआ 5 पित्तबागु में खूदवाया गया है। पित्तबागु कुए से पाइपलाइने बिछाई गई है। पित्तबागु कुए पर एक पम्प घर का निर्माण किया गया था। एक विद्युत पम्प सैट भी अधिस्थापित किया गया है और निधि पोषित स्थाओं और श्रमिक कालोनियों में पानी पम्प किया जा रहा है। पित्तबागु के द्वितीय कुए पर एक डीजल इंजन अधिष्ठापित किया गया जिससे आवश्यकता के समय द्वितीय कुए से प्रथम कुए में पानी पम्प किया जा सके। आन्ध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से छह बिन्दू सूत्र के अधीन एक दूसरी महत्वपूर्ण जलप्रदाय स्कीम जिसका स्रोत कान्हुलेन् नदी से है, थोड़ीसेल्वा खनिक ग्राम के लिए प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम की लागत 2,77,000 रु० आकलित की गई है।

आवासन

अन्नक खनिकों के लिए गृह-निर्माण की रफ्तार में तेजी लाने की दृष्टि से, अन्नक खनिकों के हेतु अल्प लागत आवासन स्कीम के अधीन साहायकी प्रतिगृह 1600 रु० से मानक प्राक्कलित लागत के 75 प्रतिशत, जो सामान्य क्षेत्रों में 6825 रु० है और कृष्णकपासी या सूनकाली मिट्टी के क्षेत्रों में 7925 रु० हैं, या निर्माण के वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, तक बढ़ा दी गई है। खान प्रबन्धों को कार्य आदेश निर्गत करने के साथ ही खुल अनुश्रेय साहायकी का 20 प्रतिशत अग्रिम अब संवेद्य है। खान प्रबन्धों को कर्मकारों से बसूल किए गए मकान भाड़े को गृहों की मरम्मत और रखरखाव पर उपयोग करने को प्राधिकृत किया गया है।

अपना घर स्वयं बनाओ स्कीम के अधीन भी एक खनिक को अनुश्रेय वित्तीय सहाय्य 400 रु० से 1500 रु० तक बढ़ा दिया गया है —जिसमें 600 रु० सहायकी के रूप में और 900 रु० व्याजमुक्त ऋण के रूप में दिए जाएंगे जो 9 वर्ष से अधिक अवधि के दौरान मासिक किस्तों में वसूली हैं। इस स्कीम के अधीन रिपोर्ट वर्ष की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में चार नया राजस्थान में 35 गृहों का निर्माण पूरे किए जा चुके हैं।

(ड) प्राणांतक दुर्घटनाओं की दशा में वित्तीय सहायता

प्राणांतक दुर्घटना लाभ स्कीम के अधीन दुर्घटनाओं में मरने वाले अन्नक खान कर्मकारों की विधवा और स्कूल जाने वाले बच्चों को निम्न-लिखित सहायता दी जाती है —

(i) 250 रु० की रकम।

(ii) केवल 25 रु० का मासिक भत्ता जो पांच वर्ष की अवधि तक संवेद्य है।

(iii) प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चा की वास्तविक लागत 15 रु० मासिक छात्रवृत्ति तक तक देय है जब तक वह (लड़का/लड़की) 15 वर्ष का वय प्राप्त कर ले या उसकी शादी हो जाए, जो भी पहले हो।

(च) उपभोक्ता सहकारी भण्डार

बिहार में करमा में, कर्मकारों को उचित दरों पर उनकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार चल रहा है। आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में चार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार खनन सम्बन्धी व्यक्तियों की जरूरतें पूरी करने रहे।

(छ) महत्वपूर्ण न्यायकलाप 1975-76

आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए 29-5-75 में कल्याण आयुक्त की नियुक्ति की गई। आवासों गृहा में भोजन और मसयान्न भोजन को अधिष्ट मनुजित बनाने के लिए उनके मान का पुनर्विचोक्त किया गया। छात्रवृत्तियों की दरों का वास्तविक व्ययों से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया है। अल्प लागत आवासन स्कीम और अपना घर स्वयं बनाओ स्कीम के अधीन दी जाने वाली सहायता की रकम बढ़ा दी गई है।

भाग 2

वर्ष 1975-76 तथा विवरण

प्राप्तियां	रु०
1 अप्रैल, 1975 का प्रारम्भिक अतिशेष	74,78,261
1975-76 वर्ष के दौरान प्राप्तियां	56,56,539

कुल	1,31,34,800
	(अनतिम)
1975-76 वर्ष के दौरान व्यय	66,00,944
	(अनतिम)
31 मार्च, 1976 को बन्धी अतिशेष	65,33,956
	(अनतिम)

भाग 3

1976-77 वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय अर्थात् —	
बजट प्राक्कलन	
प्राप्तियां	50,00,000
व्यय	65,86,000

[फा०म० जेड० 160/16/5/75-एम० III]

सी० आर० निम, अग्रय सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th April, 1977

S.O. 1214.—In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, (22 of 1946) the Central Government hereby publishes the following report of the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ended on 31st March, 1976 together with a statement of accounts for that year and an estimate of receipts and expenditure of the said Fund for the year 1976-77.

PART I

I. General.—The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) for financing schemes relating to the Welfare of Labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of customs, on all mica exported upto a maximum rate of 6-1/4 per cent ad valorem. The rate of cess which was 2-1/2 per cent ad valorem previously has been increased to 3 1/2 per cent with effect from the 15th July, 1974. The collections are allocated for expenditure on welfare measures among the various mica producing areas in proportion to their average production.

PART II

Facilities Provided

A. Medical

Fairly extensive medical facilities for mica workers and their dependents are provided free of cost by the Mica Mines Welfare Organisation. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treatment of T.B. including domiciliary treatment, dispensary services including Ayurvedic dispensaries and other facilities etc. The following central and regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisation for the treatment of mica miners and their dependents during the year under report :—

Sl. No.	Name of the Hospital	Bed Strength
1.	Central Hospital, Karma (Bihar)	100
2.	Central Hospital, Gangapur (Rajasthan)	30
3.	Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	30
4.	Regional Hospital, Tisri (Bihar)	30
5.	Regional Hospital, Talupur (Andhra Pradesh)	10
6.	T.B. Ward attached to Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	20
7.	T.B. Hospital, Karma (Bihar)	50
8.	Indoor Wards at Static Dispensaries at Almi and Bagore (Rajasthan)	5 each
7.	Regional Hospital, Sydapuram (non-dietary ward)	10

In addition, the following other medical institutions also continued to function in the three mica producing States:—

Medical Institutions	Andhra Pradesh	Bihar	Rajasthan	Total
Ayurvedic Dispensaries	3	8	8	19
Allopathic Dispensaries	1	5	..	6
Mobile Medical Units	1	3	1	5
Maternity and child Welfare/Centres	4	..	3	7
Small Community Centres	..	5	..	5

The Welfare Organisation has been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of the miners. Apart from setting up of T.B. Hospitals and clinics, six beds in the Government T.B. and Chest Diseases Hospital, Nellore continued to be reserved for the exclusive use of mica miners and their families. In the Rajasthan Region 4 beds have been reserved in T.B. Sanatorium, Madar (Ajmer). One of the Static Dispensaries at Sydapuram (Andhra Pradesh) has been ordered to be converted into a ten bedded non-dietary T.B. Hospital, and Domiciliary treatment of T.B. has been implemented from 27-12-1975.

A substance allowance of Rs. 50 per month is granted to the dependents of mica miners who receive treatment in the T.B. Hospitals set up by the Welfare Organisation for a period of six months or till the miner gets re-employment whichever is earlier in cases where there are no earning members in the Family.

Miscellaneous Medical Facilities

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from leprosy at the Tetulmani Leprosy Hospital. For the treatment of mica miners suffering from cancer arrangements continued at the Kalla Hospital, Asansol and for mental diseases at the Hospital for Mental diseases at Ranchi. A school Health programme which provides for the inspection of building and their surroundings and medical examination of the students studying in the school run by the Welfare Organisation in Andhra Pradesh, has been introduced. Other medical facilities are as under :—

1. For mica mines workers suffering from T.B. Domiciliary Treatment Scheme has been introduced from 27-12-1975.
2. Immunisation of mica mine workers against tetanus in cooperation with the concerned mine managements and Director General of Mines Safety has been taken up.
3. For the first time the Lady Doctor is going on mobile duty from 16-2-76 to the Hospitals located at Otukur Sydapuram, Talupur to take care of ante natal, postnatal care and also Family Planning programme etc.
4. For the first time in the Andhra Pradesh mica mine region, a Free Eye Camp was conducted mainly for the benefit of Mica labourers. This was inaugurated by the Minister of Labour, Government of India. It is also understood that it is also first of its kind under Welfare Organisation of Government of India. This Camp was a great success.
5. One mica worker was sanctioned benefits under Fatal Accident Benefits scheme.
6. Diet for the T.B. Subsistence patients and other patients of Central Hospital Kalichedu and Regional Hospital, Talupur has been revised in consultation with the superintendent, T.B. Hospital, Nellore to make it more nutritive.
7. Under T.B. Subsistence allowance scheme 19 applicants were sanctioned subsistence allowance.
8. On a special request made to the Government of Andhra Pradesh by this Organisation the Superintendent W.F.T.B and C.D. Hospital Nellore has started visiting Central Hospital, Kalichedu and other three Regional Hospitals and Dispensaries from March, 1976 onwards for giving specialised guidance regarding treatment of T.B. patients of T.B. Ward and also patients undergoing Domiciliary Treatment.
9. The Government of India selected Central Hospital, Kalichedu as one of the Centres under ILO for augmentation of Family Planning in this mining area.

B. Educational and recreational facilities

For providing education and recreational facilities to mica workers and their dependents, Multi-purpose Institutes each comprising of an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre are run by the Welfare Organisation. In order to expand the Adult Education activities, feeder and Adult Education Centres have also been opened by the

Welfare Organisation. The number of institution providing these facilities are as under :—

Institution	Andhra Pradesh	Bihar	Rajasthan	Total
(a) Multipurpose Institutes (with an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre)	.	9*	.	9
(b) Community Centres	1	6	.	7
(c) Centres for Women	4	4
(d) Primary and Elementary Schools	6	3	..	9
(e) Feeder Centre	.	1	..	1
(f) Middle/High School	2	4	..	6
(g) Adult Education Centres	.	9	7	16
(h) Boarding Houses/ Hospitals for Miners' Children	2	4	1	7
(i) Mobile Cinema Units	1	3	1	5
(j) Radio Sets installed in Mica Mining areas	39	16	..	55
(k) Recreational clubs	12	..	9	21
(l) Bhajan Mandalies	9	..	13	22
(m) Library and reading rooms	9	9

*Attached to Multipurpose Institute and Community Centres. All the schools of Bihar region except M.F. School, Karma, are to be handed over to the State Government.

(i) The pattern of welfare facilities provided to mica miners is not uniform. In Bihar, Multipurpose Institutes, each with an adult education centre and a Women's Welfare Centre, provide educational and recreational facilities to workers. Training in handicrafts like sewing and knitting is given to women attending these centres. Every institution serves as training-cum-production centres. Woman workers learn tailoring, stitching embroidery and lace work etc. in women welfare centres.

In Bihar, the Welfare activities at Zonal Headquarters include the following :—

- (1) Bath to children of miners
- (2) Adult education (both men and women)
- (3) Tutorial classes
- (4) Indoor games like carrom board, chess, ludo etc.
- (5) Outdoor games like volley ball, kabaddi, rope drawing etc.
- (6) Reading room with news papers, magazines, library books etc.

The Welfare activities at sub-centres are :—

- (1) Adult Education (only men)
- (2) Tutorial classes (only boys)
- (3) Indoor games
- (4) News-papers etc.

In Andhra Pradesh, the Welfare Organisation provides facilities like Community Centres for women, recreational club, etc. In community Centres tailoring/embroidery, lace work etc. is taught to the women. The work of these

Centers is supervised by the Assistant Labour Welfare Inspector and the Junior Assistant Welfare Inspector respectively.

(ii) In all the schools run by the Fund in Andhra Pradesh, the children are provided with free mid-day meals, milk, books, slates, bags, chappels and dresses. Milk and tiffin (other than cooked food) are provided to the miners' children attending the multipurposes Institutes and Community Centres in Bihar. Mid-day meals, books and slates and other stationery articles are supplied to the school going children of mica miners in Rajasthan.

(iii) For the benefit of the children of mica mine workers studying in High School away from their places of residence, boarding Houses/Hostels have been set-up by the Welfare Organisation.

(iv) Scholarships ranging from Rs. 10 to Rs. 75/- per month are granted to the children of mica miners studying in schools and colleges for prosecution of their general and technical studies. Tuition fee is also granted to school going children of mica miners in Bihar.

(v) Cinema shows are exhibited throughout the year in the mica mining areas by the Mobile Cinema Units of the Welfare Organisation. They attract large number everywhere and are very popular among the mica workers.

(vi) Games and sports are held every year in all the mica regions and prizes are awarded to the winners.

(vii) Facilities by excursion-cum-study tours are also provided. A Bharat Darshan Tour was arranged during the period under report for miners of Rajasthan region.

(viii) Kirtan and Bhajan parties are arranged to go from Centre to Centre to entertain the workers.

(ix) Radio sets have been provided for the recreation of miners and their families at all the Multipurposes Institutes/Welfare Centres run by the Fund.

C. Drinking water facilities

Scarcity of water for drinking and other purpose is a chronic problem in the Mica mining areas. The mine managements are persuaded to take up Water Supply Scheme with financial assistance up to Rs. 7,500/- or 75 per cent of the cost of this well, whichever is less.

D. Water Supply

With an aim to solve the chronic water scarcity at Kalichedu, (A.P.) a permanent Water Supply Scheme was commissioned by the Union Labour Minister, Shri K. V. Raghunatha Reddy, on 16-4-76. The sanctioned cost of the scheme is Rs. 1.426 Lakhs.

In cooperation with the Government of Andhra Pradesh under Six-Point Formula, another important water supply scheme taking its source from Kandleru river has been taken up for Thurimerla mining village. The scheme has been estimated to cost Rs. 2,77,000/-. The Government of India have sanctioned a contribution of Rs. 65,750/-. It is estimated that when the above water supply scheme is completed, it will relieve chronic water scarcity of this area.

In Rajasthan region one new well at Ganeshpura was sunk and renovating work on Ghodas well is in progress. In the Bihar region, Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation, took up construction of a Dam at the Futlaira River in the Dhorakolia, but the Scheme had to be abandoned because it could not prove to be a success due to typical conditions of the area and heavy sand deposits in the dam than expected. In Bihar 74 wells costing in all Rs. 7,40,000 approximately to the Fund have so far been sunk. Supply of drinking water on departmental truck on "No profit No Loss" basis was arranged by the Fund during the last summer. In Andhra Pradesh so far 26 wells have been sunk. With a view to resolve the water scarcity in Kalichedu village a permanent Water Supply Scheme has been sanctioned at an estimated cost of Rs. 1.426 lakhs. The work of the project is almost complete. One more well has been sunk in Pinneruvagu.

Pipelines have been laid from Pinneruvagu well. A pump house at Pinneruvagu well was also constructed. An electrical Pump-set has also been installed and water is being pumped to Fund's institutions and Labour Colonies. A diesel engine has been installed at the second well in Pinneruvagu for pumping water from the second well to the first well in time of need. In another important water supply scheme taking its source from Kandleru river, is proposed to be taken up for Turimerla village. The scheme is estimated to cost Rs. 2,77,000.

HOUSING

With a view to accelerate the tempo of construction of houses for the Mica miners, the subsidy under the low Cost Housing Scheme for the mica miners has been increased from Rs. 1,600 per house to 75 per cent of the standard estimated cost which is Rs. 6,825 in ordinary areas and Rs. 7,925 in black cotton or swelly soil areas, or 75 per cent of the actual cost of construction, whichever is less. Twenty per cent of the total admissible subsidy is now payable in advance to the mine managements with the issue of the work order. The mine managements have also been authorised to utilise the house rent realised from the workers for the repairs and maintenance of the houses.

Under the Build your Own House Scheme also, the financial assistance permissible to a miner has been increased from Rs. 400 to Rs. 1500. Rs. 600 in the form of subsidy and Rs. 900 in the form of interest free loan, recoverable in monthly instalments spread over a period not exceeding nine years. Under this scheme 4 houses have been completed in Andhra Pradesh and 35 houses in Rajasthan during the period under report.

E. Financial help in case of fatal accidents

The widow and school going children of Mica Mines Workers who die in case of accidents are paid as follows, under the fatal accident benefit Scheme :—

- (i) A lump sum of Rs. 250.
- (ii) A monthly allowance of Rs. 25 only payable for a period of five years.
- (iii) A monthly scholarship of Rs. 15 payable in respect of each school going child till he/she attains the age of 15 or is married whichever is earlier.

F. Consumers Co-operative Stores

A Central Consumers' Cooperative Stores at Karma in Bihar has been functioning to provide the workers their daily necessities at reasonable rates. In the Andhra Pradesh region, 4 Primary Consumers' Cooperative Stores continued to serve the needs of mining population.

G. Important activities during (1975-76)

A full time Welfare Commissioner has been appointed for the Andhra Pradesh region with effect from 29-5-75. The diet Scales of Boarding House and Mid-day Meals reviewed to make them more balanced. The rate of scholarships have been delinked with actual expenses. The assistance under the low cost Housing Scheme and Build Your House Scheme has been enhanced.

PART II

Statement of Accounts for the year 1975-76:—

Receipts :

Opening balance as on 1st April 1975. . .Rs.	74,78,261
Receipts during the year 1975-76. Rs.	56,56,539
Total	Rs. 1,31,34,800
	(provisional)

Expenditure during the year 1975-76	66,00,844	Provisional
Closing balance as on 31st March, 1976	65,33,956	

PART III

Estimated receipts and expenditure for the year 1976-77 i. o.

Budget Estimates :

Receipts	Rs. 50,00,000
Expenditure	Rs. 65,86,000

[F.No.Z-16016/5/75-MIL.]

C.R. NIM, Under Secy.

New Delhi, the 11th April, 1977

S.O. 1215.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Chartered Bank, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-4-77.

BEFORE THIRU T. N. SINGARAVELU, B.A., B.L.,

Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras

(Constituted by the Central Government)

Wednesday, the 23rd of March, 1977

Industrial dispute No. 36 of 1976

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Chartered Bank, Madras-1).

BETWEEN

The workmen, represented by
The General Secretary,
The Chartered Bank Indian Staff Association,
Chartered Bank Building, Madras-1.

AND

The Manager,
Chartered Bank No. 371, N.S.C. Bose Road, Madras-1.

REFERENCE :

Order No. L-12011/35/75-D.IIA, dated 6th June, 1976 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for hearing, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiruvallargal G. Venkataraman and R. Jamal Nazeem for Thiruvallargal Aiyer and Dolla, Advocates for the workmen and of Thira C. Doraswami, partner of King and Partridge, Advocates for the Management and the parties having filed a Joint Memorandum of settlement and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

This is an Industrial Dispute between the Management of Chartered Bank, Madras and their workmen in respect of the matters referred to in the Schedule. This reference was made by the Government of India in its order No. L-12011/35/75-D.IIA, dated 6th June, 1976 for adjudication.

2. The issues in the reference read as follows:

- (a) Whether the action of the management of the Chartered Bank, Madras, in refusing to fill up the existing permanent vacancies of Staff Officers from the existing panel of Special Assistants as per past practice justified? If not, to what relief the aggrieved workmen in the panel are entitled?
- (b) Whether the action of the Management of the said Bank in refusing to give officiating chances to the two qualified sub-staff at Madras, namely Sarvaswari V. Sathivelu and M. Santharajan in suitable clerical vacancies is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

(c) Whether the management of the said Bank have reported to discrimination in the matter of payment of each equivalent of unavailed/accumulated privilege leave to the heirs/dependants of the deceased workman? If so, what should be the amount payable in this regard to the heirs/dependants of the following workmen?

1. Shri D. Chandran
2. Shri G. Khader Ahmed.
3. Shri A. S. Narayana Sah
4. Shri S. Venkataswamy
5. Shri C. V. Dakshinamurthy.
6. Shri V. S. Pinagapani.

3. The Bank employees have filed a Claim Statement through their Union and they have set out the grounds in which they challenge the action of the Management in refusing to fill up the existing permanent vacancies and in refusing to give officiating chances to the sub-staff. They also press for monetary relief for the heirs of the deceased workmen.

4. The Management has filed a counter statement justifying its action and contended that the Union cannot interfere in the matter of appointments or promotions and that they are all managerial functions. They also denied discrimination in the matter of awarding relief to the families of the deceased workmen.

5. The General Secretary of the Union gave evidence as W.W.1 and spoke to the averments in the Claim Statement. The matter was adjourned for cross-examination of this witness and, on the adjourned day, both parties filed a joint memorandum of settlement into Court reporting that they had amicably settled the matter and that an Award may be passed in terms of the Settlement. I have perused the terms of the Settlement and also heard learned counsel for both parties. I am satisfied that the Settlement is fair, just and reasonable. Therefore, the Settlement is recorded and an Award is passed in terms of the Settlement. The Settlement will form part of the Award. I direct each party will bear his or its own costs.

Dated, this 23rd day of March, 1977.

Sd/-

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

I.D. 36 of 1976

In the matter of an Industrial Dispute between the Workmen and Management of The Chartered Bank, Madras.

The parties to this dispute have settled the same as per the Memorandum of Settlement annexed hereto marked 'A' and pray that this Hon'ble Court may be pleased to make an Award in terms of the said settlement.

Dated at MADRAS, this 21st day of March, 1977.

Sd/- Illegible

Advocate for

The Union

Sd/- Illegible

Advocate for

The Chartered Bank

'A'

FORM H

Memoandum of Settlement under Section 2(p) of the Industrial Disputes Act and Rule 58 of the Industrial Disputes (Central) Rules 1957.

Name of parties :

Representing Employer—Mr. S. R. Mehta, Manager, The Chartered Bank, Madras and Mr. R. Subramanian, Assistant Accountant, The Chartered Bank, Madras,

Representing Workmen—Mr. L. Joseph, President and Mr. M. S. Dawood, General Secretary, Chartered Bank Employees Union, Madras.

SHORT RECITAL OF THE CASE:

Whereas by an order of the Central Government No. L. 12011/35/75/D II(A) dated the 6th June 1976 the following issues were referred to the Central Government Industrial Tribunal:—

1. Whether the action of the Management of The Chartered Bank, Madras, in refusing to fill up the existing permanent vacancies of Staff Officers from the existing panel of Special Assistants as per past practice is justified? If not, to what relief the aggrieved workmen in the panel are entitled.
2. Whether the action of the Management of the said Bank in refusing to give officiating chances to the two qualified sub-staff at Madras, namely Sarvaswari V. Sathivelu and M. Santharajan in suitable clerical vacancies is justified, if not to what relief are the said workmen entitled?
3. Whether the Management of the said Bank have resorted to discrimination in the matter of payment of cash equivalent of unavailed accumulated privilege leave to the heirs/dependants of the deceased workmen? If so, what should be the amount payable in this regard to the heirs/dependants of the following workmen:

1. Shri D. Chandran.
2. Shri G. Khader Ahmed.
3. Shri A. S. Narayana Sah.
4. Shri S. Venkataswamy.
5. Shri C. V. Dakshinamurthy
6. Shri V. S. Pinagapani.

And whereas the said dispute was numbered as I.D. No. 36 of 1976 by the said Tribunal presided over by Shri T. N. Singaravelu.

And whereas during the pendency of the said dispute the parties have had negotiations with a view to improve, foster and sustain cordial industrial relations as a result of which it was agreed as follows:

TERMS OF SETTLEMENT

1. Notwithstanding anything done in the past the workmen recognise and agree that promotion from clerical grade to Staff officer cadre will be in the discretion of the Management subject to the provisions of para 529 of the Sastry Award.

2. The workmen further recognise and agree that the "existing panel of special assistants" (referred to in the Order of Reference) was set up for the limited purpose of giving officiating opportunities as Staff Officers for the persons listed therein during the leave vacancy. Therefore the workmen drop their demands in relation to the first issue in the Order of Reference.

3. The workmen recognise and agree that the following clause:

"OFFICIATING OPPORTUNITIES TO THE SUB-STAFF

The sub-staff who have passed Matriculation or equivalent examination thereof from a recognised Education Board/University or typing examination will be permitted to officiate in suitable clerical leave vacancy. However the affording of officiating opportunities will not mean automatic promotion to clerical cadre."

In the Memorandum of Settlement dated 29th September 1972 between the Chief Manager of the Bank and the All India Chartered Bank Employees Federation, on which the claims made by the workmen under the second issue of the

Order of Reference are based, was in connection with officiating chances in the clerical cadre for the sub staff who had at that date acquired the necessary qualifications and was not intended to cover any sub-staff who thereafter acquired the necessary qualifications. The workmen therefore drop their demand in relation to Issue No 2 in the Order of Reference

4 The Union recognise and agree that in accordance with the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 Clause No 13 b when an employee ceases to be in service whether by retirement, resignation or death, the unavailed privilege leave lapses and there can be no encashment of such leave. The workmen therefore drop their demand under Issue No 3 in the Order of Reference and are pleased to note that the Management is prepared to pay a lump sum of Rs 1,000 on humanitarian grounds to the heirs/dependants of the six deceased employees named in the Order of Reference

5, It is agreed that in connection with issues or points of difference that may arise between the parties in future every endeavour will be made by them to settle these by mutual discussions/negotiations and/or by use of proper legal machinery for settlement of disputes. Both sides will not take any action that will affect the smooth working of the Bank

6 It is the intention of both the parties that this settlement be filed before the Tribunal and pray that the Tribunal make a Consent Award in terms hereof

7 It is the intention of the parties that this Settlement shall continue to be binding on them until and unless modified or altered by any industrywise Award/Settlement binding on the parties

Dated this 21st day of March, 1977 at Madras

WITNESSES

1 S L Banerjee	For and on behalf of
2 C G K Bhupathi	The Chartered Bank, Madras
	S R Mehta
	R Subramanian
	For and on behalf of
	Chartered Bank
	Employees Union, Madras

WITNESSES

1 L Lakshminpathy	L Joseph
2 T E Kumaraswamy	M. S. Dawood
	[No 12011/35/75 D II A]
	T N SINGARAVENU, Presiding Officer
	R P NARUI A, Under Secy

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1977

कां०भा०1216 — भारत क तारीख 25 दिसम्बर, 1976 के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 4548 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां०भा० 4862 तारीख 7 दिसम्बर 1976 में पृष्ठ 4548 पर कालम एक की—

(i) पंक्ति 5 में "जुलाई" का "जून" पढ़ें।

(ii) पंक्ति 6 में "बैकिंग उद्योग" को "बैकिंग उद्योग, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित बैकिंग कम्पनी द्वारा चलाया जाता है" पढ़ें।

[सं० एम०-11017(7)/76-डी।ए०।]

एस० एच० एस० अय्यर, डेस्क अधिकारी

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th April, 1977

S.O. 1216.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 4862 dated the 7th December, 1976, published at pages 4548-49 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 25th December 1976, at page 4549 in column one, in line 2,—

(i) for 'July' read "June"

(ii) for "Banking Industry" read 'banking industry, carried on by a banking company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act'

[No S 11017/7/76/DI A]

S H S IYER, Desk Officer

New Delhi, the 13th April, 1977

S.O. 1217—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No 1 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ganhoodih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, Dist Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th March, 1977

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1, DHANABAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 3 of 1976

(Ministry's Order No L-20012/129/76/DIHA, Dt 6-9-1976)

PARTIES

Employers in relation to the management of Ganhoodih Colliery of M/s Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia, Distt Dhanbad

AND

Their Workmen

PRESENT

Mr Justice K B Srivastava (Retd) Presiding Officer

APPEARANCES

For the Management—Shri A K Pal, Area Personnel Manager, Area No IX, BCC Ltd, and Shri V R Joshi, Asstt Personnel Manager, Area No IX, BCC Ltd

For the Workmen—Shri S Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, and Shri Mahadeo Mahato, the workman concerned

STATE Bihar

INDUSTRY Coal

Dhanbad, dated, the 25th, March, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, the referred the following dispute for adjudication to this Tribunal, namely—

"Whether the action of the management of Ganhoodih Colliery of M/s Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia (Distt Dhanbad) in dismissing Shri Mahadeo Mahato, Munshi, from service, with effect from 1st March, 1976, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The parties have entered into a mutual settlement whereby they have resolved their dispute. The settlement is an annexure to this award and I think that the settlement is reasonable and proper.

3. My award is that the dispute stands settled in terms of the settlement which is an annexure to and shall form part of the award.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD
In Ref. No. 3 of 1976

Employers in relation to Ganhoodih Colliery

AND

Their workmen represented by Rashtriya Colliery
Mazdoor Sangh.

Joint Petition of Compromise Settlement

The humble petitioners, on behalf of the parties above-named, most respectfully beg to state, that the instant dispute has been amicably settled between the parties on the terms stated below:—

Terms of Settlement :

1. The Parties agree that Shri Mahadeo Mahato will be reinstated in his respective post at either Kuya or Golukdih Colliery of Bharat Coking Coal Limited within 15 days of his reporting for duty to the General Manager. Area No. IX.

2. The Parties agree that the continuity of service of the workman shall be maintained, and the period of their idleness, from the date of dismissal to that of reinstatement shall be treated as leave without pay for the purpose of calculating earned leave and bonus.

3. The Parties agree that they shall have no other claim whatsoever, against each other, on account of the present dispute, which stands fully and finally resolved by this settlement.

4. The management agrees to pay Rs 200 to the workman/Union concerned towards cost.

The petitioners pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the above settlement, and to pass award, in terms thereof.

For Management :

1. Shri A. K. Pal,

Area Personnel Manager,

Area No. IX., B.C.C. Ltd.

2. Shri V. R. Joshi,

Asstt. Personnel Manager,

Area No. IX., B.C.C. Ltd.

For Workmen :

1. Shri S. M. Bose,

Secretary, Rastriya

Colliery Mazdoor Sangh.

2. Shri Mahadeo Mahato

Dated, the 25th March, 1977.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-20012/129/76-D IIIA]

S.O. 1218.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Sinidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th March, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 20 of 1975

(Ministry's Order No. L-20012/163/74-LRII/DIIIA,

Dated 26-3-1975)

PARTIES :

Employers in relation to the management of North Sinidih Colliery (Section of Jogidih Colliery) of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice K. B. Srivastava (Retd.), Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Management—Shri Prasant Buiyan, Asstt. Law Officer.

For the Workman—Shri Jagadamba Prasad Tiwary, the workman concerned.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated, the 22nd March, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of North Sinidih Colliery (Section of Jogidih Colliery) of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad, is justified in stopping Shri Jagadamba Prasad Tiwary, Bill Clerk, from work, with effect from 17-6-1974? If not to what relief is the workman entitled?"

2. Usual notices were issued requiring the parties to file their respective written statements. The workman Jagadamba Prasad Tiwary filed his written statement on May 27, 1975. The Bharat Coal Limited filed its written statement on June 4, 1976. Jagadamba Prasad Tiwary filed a rejoinder to the written statement of the Bharat Coking Coal Limited and also a supplementary written statement on June 28, 1976. The Bharat Coking Coal Limited filed its rejoinder to the two written statements of Jagadamba Prasad Tiwary on July 22, 1976.

3. The case of the workman, as set out in his original written statement dated May 27, 1975, is that he was a permanent employee of the North Sinidih Colliery and was working as Office Superintendent whose duty it was to prepare wage-sheets and to make payments. He continued to work on that post till June 17, 1974 when the Manager of the Jogidih Colliery (in which the North Sinidih Colliery had merged) stopped him from work. In spite of stoppage of work, however, he continued to sign the Attendance Register till June 30, 1974 when he was stopped from doing even that after that date. He alleges that he had qualified himself for membership of the Coal Mines Provident Fund and was also contributing to that fund. He has assailed the action of the management in stopping him from work with effect from June 17, 1974 on a variety of grounds, namely, (1) stopping from work amounts to termination of service which can be effected only after strict compliance with the Standing Order No. 13C, which requires the giving of a notice and one month's salary but none of these two conditions was fulfilled in his case. (2) stopping him from work was discriminatory inasmuch as while 60 per cent of workmen, similarly situated as him, were continued in service, his services were terminated; (3) he was victimised because he had made charges of corruption against the Unit Manager and while the corruption charges were dropped, he was victimised by termination of his services; (4) he had become a workman by having worked for the requisite period under the Model Stand-

ing Order, Scheduled 1A, Section B and as such his services could not have been terminated without compliance with the provisions of the Standing Order; and (5) stopping him from work was unjustified, malafide, discriminatory and violative of the principles of natural justice. He has, therefore, prayed that the action of the management be held to be unjustified he should be reinstated as Bill Clerk or Office Superintendent with retrospective effect from the date of termination, namely, June 17, 1974 and with continuity of service; and full back wages and other monetary benefits be also awarded to him.

4. The case of the Bharat Coking Coal Limited is that the management of the North Sinidih Colliery, a non-coking coal mine, was taken over on January 31, 1973 and the coal mine was nationalised on May 1, 1973 and thereafter it was merged in the Jogidih Colliery. Jagadamba Prasad Tiwary was not a workman as he was not in the employment of the North Sinidih Colliery on the date of taking over or on the date of nationalisation, and as such he was not a taken over employee. It is alleged that he started working as a Night Guard from November 12, 1973 on the basis of a slip issued by the Assistant Manager of the Colliery, without the prior approval of the authority competent to employ a new hand. His appointment was also not notified to the appointing authority and his name was not entered in the approved man-power list of the colliery. It is also alleged that under the rules of the Bharat Coking Coal Limited, no one can be a workman unless his name is either entered in the approved man-power list or a letter of appointment is issued to him under the orders of the appointing authority. On obtaining satisfaction that Jagadamba Prasad Tiwary was an inductee and not a genuine workman, the Bharat Coking Coal Limited stopped him from work from June 17, 1974. It has also been pleaded that Jagadamba Prasad had worked for a total of 187 days spread over a period of 7 months and had not become a workman and as such no notice or notice pay was required to be given to him when he was stopped from work. It is denied that there was any malafides or victimisation or unfair labour practice as the services of all inductees were terminated and not only that of Jagadamba Prasad Tiwary. Lastly, it is pleaded that Jagadamba Prasad Tiwary is not entitled to any relief because the action of the management in stopping him from work was justified.

5. Jagadamba Prasad Tiwary, in his rejoinder dated June 28, 1976, has asserted that his name was entered in the original register Form B and in the original man-power list but the Bharat Coking Coal Limited has destroyed these documents and has fabricated new ones. He has further alleged that the competent appointing authority had actually sent a letter to the manager of the colliery for giving an appointment to him but the Bharat Coking Coal Limited has destroyed that letter after the tussle arose between him and the Bharat Coking Coal Limited. He has also alleged that bonus used to be paid to him. The rest of the pleas taken in the rejoinder are mere repetitions of the pleas already taken in his original written statement.

6. In his supplementary written statement, he has alleged that he himself had prepared the original Form B Register and the original man-power list before the management of the Colliery was taken over and before he proceeded on leave in the last week of January, 1973. He has then stated that he returned from leave in the second week of February, 1973 and made a written application for employment and was assured by the officers that he would be given an employment. As a result of that, the competent authority approved his appointment and conveyed his approval to the Sub-Area Manager and the latter conveyed it in writing to the Manager of the Colliery. The Sub Area Manager on looking to his physique, had told him that he looked like a Night Guard and had advised M. Khaitan, the Manager of the Colliery, to appoint him as a Night Guard with a promise that he would be given a higher post in due course of time. He was thus appointed as Night Guard in November, 1973. Thereafter, Dadu Ram, the Bill Clerk, went on leave and he was appointed a Bill Clerk in his place and continued to work as such even after the return of Dadu Ram from leave. He has again raised the same old pleas of victimisation etc.

7. The Bharat Coking Coal Limited in its rejoinder dated July 22, 1976, averred that Jagadamba Prasad Tiwary became a member of the Coal Mines Provident Fund only in 1974. It is also pleaded that the Standing Orders apply only to workmen and not to rank outsiders or inductees and, therefore, there was no question of giving any notice or any notice pay

to Jagadamba Prasad. It has controverted the other allegations made by Jagadamba Prasad Tiwary, e.g., in respect of discrimination or fabrication of records, victimisation etc.

8. On the various controversies in the case, the Bharat Coking Coal Limited has examined four witnesses, namely, M. P. Gupta MW-1, Dipak Biswas MW-2, Mohan Khaitan MW-3 and Jamuna Prasad Singh MW-4 and has further placed reliance on five documents Exts. M-1, M-2, M-3, M-4 and M-5. The workman Jagadamba Prasad Tiwary has examined three witnesses Bidhyut Dutt WW-1, M. P. Baliati WW-2 and himself as WW-3 and has also taken his stand on 92 documents Exts. W-1 to W-92.

9. North Sinidih Colliery was a non-coking coal mine, whose owner was one Sankarlal Kejrilal of Khatiasgarh. The management of this colliery, as well as of all non-coking coal mines, with the exception of a few captive mines of TISCO and IISCO, was taken over by Custodians on January 31, 1973 under Section 3 of the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973. North Sinidih Colliery is enumerated at serial No. 79 of the Schedule to the Ordinance. This ordinance was subsequently replaced by Coal Mines (Taking over of Management) Act, 15 of 1973. All such coal mines were subsequently nationalised under section 3 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 on and from May 1, 1973. North Sinidih Colliery is entered at serial No. 134 of the Schedule to the Coal Mines (Nationalisation) Act. It is not disputed that, for the sake of convenience and better management, North Sinidih Colliery was merged in the Jagidih Colliery; nor is it disputed that Bharat Coking Coal Limited, a Government Company, stood vested with the right, title and interest of Sankarlal Kejrilal, the quondam owner of the colliery.

10. The case of the workman is that he became an employee of the North Sinidih Colliery during the period of ownership of the previous owner, a fact which has been seriously contested by the Bharat Coking Coal Limited. The workman has deposed as WW-3 that he joined as an employee of the North Sinidih Colliery in January, 1970. His place of work, however, was not fixed as Sankarlal Kejrilal either kept him as a domestic servant at his residence at Jharra for 2 or 3 months in a row or posted him to work in the colliery itself, at his sweet will and choice. However, since July 1972, he always worked in the colliery itself and the workers used to address him as Office Superintendent. I am not inclined to believe his ipse dixit. He admits in cross-examination that Sankarlal Kejrilal did not issue any letter of appointment and explains it by saying that no such letters were ever issued. There is no documentary evidence also in support of his assertion. Section 48(1) of the Mines Act says that for every mine there shall be kept in the prescribed form and place a register of all persons employed in the mine showing in respect of each such person—(a) the name of the employee with the name of his father etc. and such other particulars as may be necessary for purposes of identification, (b) the age and sex of the employee, (c) nature of employment (whether above ground or below ground and if above ground, whether in open cast workings or otherwise) and the date of commencement thereof, (d) in the case of an adolescent, reference to the certificate of fitness granted under Section 40 and (e) such other particulars as may be prescribed; and the relevant entries shall be authenticated by the signature or the thumb-impression of the person concerned. Section 48(3) says that no person shall be employed in a mine until particulars required by Section 48(1) have been recorded in the register in respect of such person etc. Section 48(4) says that for every mine....., there shall be kept in the prescribed form and place separate registers showing in respect of each person employed in the mine—(a) below ground, (b) above ground in open cast workings; and (c) above ground in other cases—(i) the name of the employee; (ii) the class or kind of his employment; (iii) where work is carried on by a system of relays, the shift to which he belongs and the hours of the shift. Rule 78 says that the Register required by Section 48(4) of persons employed in the mine above ground other than in open cast workings shall be maintained in Form E. Thus, every coal mine has to maintain two registers in respect of an employee who works above ground other than in open cast workings; and those two registers are those prescribed in Forms B and E. Form B register has to contain entries in respect of all employees, irrespective of the fact as to whether they are working below ground or above ground in open cast workings or above ground otherwise but Register E is only in respect of such employees as work above ground other than in open cast workings.

Ext. M-1 is the Register in Form B for North Sindih Colliery for the year 1972.

It appears that there were 481 employees in this coal mine in that year. There is no mention of the name of Jagadamba Prasad Tiwary at any place in this register. This register was proved by M. P. Gupta MW-1, who was the Manager of the Colliery from May 1, 1972 to June 30, 1973. It was also proved by Jamuna Prasad Singh MW-4, the Head Clerk of the Colliery. Jamuna Prasad Singh has deposed that the entries in this register from serial no. 1 to 40 and from 252 to 481 are in his handwriting. The other entries are in the handwriting of another clerk. The omission of the name of Jagadamba Prasad Tiwary from this important register is significant and is a pointer to the fact that he was not in employment in the North Sindih Colliery at all in the time of the previous owner. Jagadamba Prasad Tiwary argued that Ext. M-1 is not the original Form B Register. According to him, he himself had prepared the original Form B Register and each page of that register bore his signature and M. P. Gupta MW-1, the then Colliery Manager, had also signed the original. That Register, according to his statement, was, however, got deliberately burnt and Ext. M-1 was got fabricated and forged by S. S. Mitra, the Senior Personnel Officer through the agency of Jamuna Prasad Singh and another clerk by making them believe that the original was lost or mis-placed. He admits that the original was not put to flames in his presence and his knowledge about it is based on hearsay. M. P. Gupta MW-1 has deposed that he was the Manager of the Colliery from May 1, 1972 to June 30, 1973. He further stated that he does not know Jagadamba Prasad by name or face and when Jagadamba Prasad was pointed out to him he stated that he did not know him at all and that he was not an employee in the colliery during the period that he was its manager. I have no reason to dis-believe this highly responsible and independent officer. It follows that if Jagadamba Prasad was not even in employment in the colliery between May 1, 1972 and June 30, 1973, he could not have been entrusted with the task of preparation of register Form B. He is a highly interested witness and can say anything to benefit himself. Besides, there is no reason why the most vital document of a mine should be destroyed. It contains the history of all workmen and the management would not like to destroy such an important document to the disadvantage of all its genuine employees in order to exclude one workman in particular. Ext. M-1 does not appear to have been fabricated at all. On the first page there is a mention that this register was seized by the custodian at the time of take over. The certificate is signed by one V. Sinha under April 17, 1975. Each page is signed by the clerk who is described as Register Keeper. Each workman has either put his thumb impression or signature against his name. Jamuna Prasad Singh MW-4 has given his sworn testimony that most of the entries are in his handwriting. It is true that it is not signed by the colliery manager but there is no provision for it in the register. On the last page there is the endorsement "Seen" given by the Labour Enforcement Officer (Central) under date December 17, 1972. It is impossible to believe that 481 workmen and the Labour Enforcement Officer and V. Sinha all conspired together to forge a document. Another criticism of Jagadamba Prasad Tiwary is that one R. C. Sharma, Bineswar Singh, Mira Yadav, Sheomoni Yadav and Baliram Singh were workmen during the regime of the previous owner but their names are also omitted from Ext. M-1 and it is quite likely that by some inadvertence, his name was also omitted. Mohan Khaitan MW-3 was cross examined from this aspect. He was the Manager of the colliery from October 1973 to October 1974. He stated that R. C. Sharma, Bineswar Singh and Mira Yadav were workmen but their names are not entered in Ext. M-1, though the name of Baliram Singh is entered at serial No. 278. He also stated that in the same manner, the name of Jagadamba Prasad might also have been omitted. Great stress was placed by Jagadamba Prasad on this admission but I am not prepared to attach any weight to it. Mohan Khaitan was not in this colliery during the regime of the previous owner and, therefore, his evidence is not based on personal knowledge; it is more speculative and conjectural than based on reality. The next man tackled with regard to it is Jamuna Prasad Singh MW-4. He stated in cross-examination that the name of Baliram Singh is entered at serial no. 278. He further stated that there was another man bearing the same name but his name is not entered in Ext. M-1 because he was not in employment in that year. With regard to R. C. Sharma, Bineswar Singh, Mira Yadav and Sheomoni Yadav, he stated that they were

in service before the date of take over but their names are not entered in Ext. M-1. It is quite possible that these persons entered into employment some time in January, 1973 during the time of the previous owner whose right, title and interest continued till May 1, 1973 when it came to vest in the Bharat Coking Coal Limited. Their names might find a mention in register Form B for 1973 but that is not on the record to verify the matter. Jagadamba Prasad Tiwary has claimed to have served Sankarlal Kejilal personally also at his residence in Jhatia for months together. He could have summoned him to state that he had employed him in his colliery but he was not called. He could have summoned any other workmen of the colliery to support his case but this was also not done. He chose to place reliance upon the statement of one Narain Pandey which is Ext. W-83 made during the course of a domestic enquiry against R. Singh, the Asstt. Manager of the colliery. It appears that a slip of paper purporting to have been signed by R. Singh was given to the Bill Clerk on 12-11-1973 reading "Bill Clerk, North Sindih Colliery. Please allow Jagadamba Prasad Tiwary (Night Guard) on 12-11-73." It is said that it is R. Singh who had on the basis of that slip inducted Jagadamba Prasad as a Night Guard in the colliery for the first time on November 12, 1973. For that induction, R. Singh was charge-sheeted for having manoeuvred to induct him in employment in an un-authorised manner. Ext. W-24 is the enquiry report of M. P. Bahasi who was the Enquiry Officer and who has been examined in this reference as WW-2 by Jagadamba Prasad. In the enquiry report, M. P. Bahasi reported that the slip was forged and the signature of R. Singh on that was also forged and he, therefore, held that the charge was not established against him. During the course of the domestic enquiry Narain Pandey, Overman, was examined as a witness. He had deposed: "Tiwary was irregularly working during the time of erstwhile owner. At the time of take over, he was not there. He came 2/3 months after take over." Jagadamba Prasad Tiwary urged that the statement of Narain Pandey clearly shows that he had been working since the regime of the previous owner though irregularly. I am of the view that neither Ext. W-24 nor Ext. W-83 are relevant in the present case. Jagadamba Prasad Tiwary was not a party to the domestic enquiry. He was not examined in the domestic enquiry. The proceedings of that enquiry and the report are not binding upon him. At best, the report can be read as a piece of document showing that R. Singh was charge-sheeted on a particular charge and was found to be not guilty. The statement of Narain Pandey is wholly inadmissible in evidence. The Bharat Coking Coal Limited had no opportunity to cross-examine Narain Pandey in this reference. Narain Pandey has not been called as a witness by Jagadamba Prasad Tiwary and his evidence in the domestic enquiry cannot be read as evidence in the reference before me. Jagadamba Prasad Tiwary, on his own admission, was not a member of the Coal Mines Provident Fund in 1972. He has not called the Bonus Register for 1972 to prove that he was in employment and was paid bonus. On a consideration of all these facts, therefore, I am certain that Jagadamba Prasad Tiwary was not in employment in the colliery in 1972 or in any earlier year.

11. His next point is based on the provisions of Section 14 of the Coal Mines (Nationalisation) Act. This section says that every person who is a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, and has been immediately before May 1, 1973, in employment of a coal mine shall become on and from May 1, 1973, an employee of the Government company in which the right, title and interest of such mine have vested, and shall hold service in the coal mine with the same rights to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the rights in relation to such coal mine had not been transferred to, and vested in the Government company, and continue to do so unless and until his employment in such coal mine is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions of employment are duly altered by the Government company. His contention is that he was in the employment of the North Sindih Colliery immediately before May 1, 1973 and, therefore, by the force of Section 14 he continued to be in employment and shall continue to do so till other orders are passed. Now, what is the evidence regarding this contention, namely, whether or not he was a taken over employee. Mohan Khaitan MW-3 was the Manager of the Joghidi Colliery from October 1973 to October 1974. He has stated that he did not appoint Jagadamba Prasad Tiwary but nevertheless he had started working in the colliery without any order of appointment. On discovering that he was an in-

ductee, he made an enquiry and the attendance clerk produced a slip signed by R. Singh, the Asstt. Manager, as the authority for the employment of Jagadamba Prasad and for that R. Singh was chargesheeted and a domestic enquiry was held. He further stated that on discovering this fact of un-authorised employment, he stopped Jagadamba Prasad Tiwary from working by a verbal order on June 17, 1974. Jagadamba Prasad Tiwary WW-3 has deposed that he was already in employment before January 31, 1973 but about 7 or 10 days before that, i.e., about January 21, 1973 he went away to his native village and on return reported to the colliery manager for resumption of duty but Mohan Khaitan expressed his helplessness in giving him any appointment and said that the Register Form B had already been seized by the custodian and he, therefore, should make direct application to the custodian. Jagadamba Prasad Tiwary accordingly made one such application. There was endless delay in taking a decision by the custodian. He, therefore, approached the Sub-Area Manager and the latter gave an oral direction that he should go and report himself to Mohan Khaitan. He went and reported to him on November 11, 1973 and was taken on duty on the following day on November 12, 1973. He worked as Bill Clerk from December 1973 to June 17, 1974 when he was stopped from work. Between November 12, 1973 and December 1973. However, he had worked as Night Guard only. S. S. Mitra, the Senior Personnel Officer, had assured him that he should work as Night Guard but he would later accommodate him at a clerk in the Office and when Dudu Ram, the Bill Clerk, was transferred to another colliery, he was appointed as Bill Clerk in his place. On the oral evidence, therefore, it appears that he started working in the colliery for the first time on November 12, 1973 long after May 1, 1973 and, therefore, Section 14 will have no application because he was not in employment of the coal mine immediately before the appointed day but came into employment long after that day.

12. The next question is as to whether he was given an employment in the sense that the Bharat Coking Coal Limited was conscious of the fact that it was appointing a new hand or Jagadamba Prasad Tiwary just started working as an inductee without a proper appointment. I would like to discuss some documentary evidence first before revealing to the oral evidence with regard to it. Dipak Biswas MW-2, Personnel Officer, Jogidih Colliery, proved Ext. M-3 and M-4, the man-power lists of the North Sinidih and Jogidih Collieries. These lists were proved on the basis of their originals. His cross-examination shows that the originals were prepared on the basis of register Form B maintained by the previous owner and these lists contain the names of all workmen who were in employment from before January 31, 1973. He denied the suggestion that Ext. M-3 and M-4 were forged documents. These two documents show the man-power strength as on August 1, 1973. The originals are signed by R. S. Rungta who was the Manager of the colliery before Mohan Khaitan MW-3, and by Mohan Khaitan, and also by R. P. Agarwal who succeeded Mohan Khaitan. Each page of the originals of Ext. M-3 and M-4 is signed by each one of these three managers. None of these lists contains the name of Jagadamba Prasad Tiwary as an employee as on August 1, 1973. The duty of the manager lay only in preparing the man-power lists and the power to approve them vested in the Sub-Area Manager, Sri Kolay. The omission of the name of Jagadamba Prasad Tiwary from the two man-power lists prepared on August 1, 1973 will clearly show that he was not in employment even till August 1, 1973. Ext. M-2 is the extract of the Bonus Register of North Sinidih Colliery for the year 1973. It shows that Jagadamba Prasad Tiwary started working in the colliery from November 12, 1973 and was paid bonus for 43 days work between the period November 12, 1973 to December 31, 1973. The total bonus paid was Rs. 21.50. Ext. M-5 is the extract of register Form B for the year 1973 and this also shows that Jagadamba Prasad Tiwary was entered in register Form B at serial No. 288. The date of commencement of employment, however, is missing. Ext. M-15 is the wage-sheet for the week ending November 12, 1973. The original page 25 of this wage-sheet was closed after serial No. 17. This page deals with casual labour and shows that 17 casual workmen were working on that date. Their total basic wages came to Rs. 222.50 and variable dearness allowance to Rs. 140.26, the underground allowance to Rs. 3.63 and the gross wages to Rs. 366.89. Another person's name was added after all these tallings at serial No. 8. Originally that name read as 'Jagdish' but 'Jagdish' was over-written

later as 'Jagdiaba' but Jagadamba Prasad Tiwary asserts that it is not 'Jagdiaba' but Jagdamba. The words 'P. Tiwary' were added after the original 'Jagdish' was corrected into 'Jagdiaba'. His attendance was shown for one day on November 12, 1973; his basic wages as Rs. 5; his variable dearness allowance as Rs. 3.08 and gross wages as Rs. 8.06. A fresh totaling was then done. Jagadamba Prasad is an educated person and had worked as Bill Clerk for some time but he has not signed against his name and what he has done is to have put an illegible thumb impression. Why should he have done it if he was regularly appointed on a permanent basis? Why should he have been shown as casual workman on daily wages if he was permanently appointed as a monthly-rater. The entry appears to have been added later after the slip purporting to bear the signature of R. Singh had been procured. Exts. W-18, W-22, W-65 and W-66 are other wage-sheets for weeks ending December 3, 1973, December 31, 1973, June 10 1974 and June 17, 1974 respectively. He has signed these wage-sheets. Ext. W-13 is the bonus register for 1974 which shows that he had worked as Night Guard from January 7, 1974 to March 31, 1974 for a total period of 83 days in the first quarter of the year and had been paid a bonus of Rs. 43.21 and had worked for a total period of 68 days in the second quarter between April 9, 1974 to June 10, 1974 and had been paid a bonus of Rs. 34. Ext. W-11 is the register Form E which shows that he had worked during the weeks 13-11-73 to 19-11-73; 20-11-73 to 26-11-73; 27-11-73 to 3-12-73; 4-12-73 to 10-12-73; 11-12-73 to 17-12-73; 18-12-73 to 24-12-73 and 25-12-73 to 31-12-73 as Night Guard. Ext. W-4 is the register Form E for the week 8-1-74 to 14-1-74. His designation is mentioned as Night Guard. Ext. W-6 is register Form E for the period 22-1-74 to 28-1-74; 5-2-74 to 11-2-74; 19-2-74 to 25-2-74; 5-3-74 to 11-3-74 and 19-3-74 to 25-3-74 during all of which period he had worked as Night Guard. The documentary evidence thus clearly establishes that he started working in the colliery not earlier than November 12, 1973. In his cross-examination, Jagadamba Prasad Tiwary admitted that he was not present in the colliery on the date of take over on January 31, 1973. He says that he was present at his native village on leave though only oral leave was granted. He admits that when he came to the colliery on return from leave, the manager refused to allow him to join. He then says that he made an application to the custodian. He has not filed a copy of that application. He admits that a screening committee was appointed to screen the cases of doubtful employees but he made no application to the screening committee claiming to be a genuine employee. These salient facts indicate that he was not present in the colliery before November 12, or else he would have made an application for resumption of duty or he would have approached the A.I.C. (C) or raised an industrial dispute. He then stated that the Sub-Area Manager gave him an oral direction on November 12, 1973 and also wrote a letter to the colliery manager to give him an appointment. He has not summoned that letter. He also admitted that Mohan Khaitan, the Colliery Manager, passed a written order for his appointment and he has got a copy of that but he has not filed that letter. He admits that he was not a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme in 1973. He examined M. P. Baliast as WW-2 but instead of supporting his case he has stated that he was an inductee. I am, therefore, convinced that Jagadamba Prasad Tiwary entered employment in a clandestine manner in conspiracy and collusion with some official or the other on November 12, 1973 and continued to work as Night Guard and for some time as Bill Clerk thereafter. The Manager believed him to be a genuine workman but the game was exposed and Mohan Khaitan stopped him from working. I am of the view that the action of the management in stopping him from work was justified because he was a rank intruder who entered employment in a collusive and fraudulent manner. He did not become a workman at all.

13. It now remains to consider the other points raised by Jagadamba Prasad Tiwary, namely, discrimination, violation of the Standing Order and victimisation.

14. With regard to his plea of discrimination, his contention is that, like him, there were others who were allowed to continue to work but his services were discharged. Mohan Khaitan MW-3 stated in cross-examination that when he checked the man-power list, he found that about 16 persons were working without authority and he stopped all of them from working without exception, after obtaining the approval of the Sub-Area Manager and likewise he stopped Jagadamba

Prasad Tiwary also after he had satisfied himself that he was an inductee. Jagadamba Prasad WW-3 deposed that one R. K. Prasad was the Dy. Personnel Manager and though his real brother S. K. Prasad was never in employment he was taken in employment after the date of take over. Assuming this to be so, there was no bar on the Bharat Coking Coal Limited from employing anyone it liked. In so far as he is concerned, there is the definite statement of Mohan Khaitan that no discrimination was made. Jagadamba Prasad then brought to my notice Ext. W-88 to prove discrimination. It appears that a reference—Reference No. 42 of 1975—was pending in Industrial Tribunal No. 2 at Dhanbad in which 8 workmen of East Sinidih Colliery were involved. Ext. W-88 is the petition of compromise in that reference filed by the parties. According to the compromise, Bharat Coking Coal Limited agreed to provide employment to these 8 workmen in any of its collieries. This will not prove any discrimination inasmuch as Jagadamba Prasad was in the North Sinidih Colliery and he cannot be compared with a workman in the East Sinidih Colliery.

15. His case with regard to the violation of the Standing Orders is based on Order No. 13 Standing Order No. 13(a) says that for termination of services of a permanent workman having less than one year of continuous service, notice of one month in writing with reasons or wages in lieu thereof shall be given by the employer. It has been seen above that Jagadamba Prasad Tiwary had entered employment in a fraudulent manner and, therefore, he did not become a workman, much less a permanent workman and, therefore, Standing Order No. 13(a) will not apply. Standing Order No. 13(b) says that no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workman provided that a temporary workman, who has completed three months continuous services, shall be given two weeks' notice of the intention to terminate his employment if such termination is not in accordance with the terms of the contract of his employment. It is not the case of Jagadamba Prasad Tiwary that he was in temporary service. The history narrated above shows that he was an inductee and he cannot be permitted to take advantage of the Standing Order which applies to workmen. No notice of termination was necessary; and indeed, the inductee was only stopped from working further when the act of induction came to notice.

16. Finally, it remains to consider his plea of victimisation. He wrote the letter Ext. W-89 to Sri K. C. Pant, Minister of Energy, Government of India, on November 2, 1974. A copy of that letter was sent to the Prime Minister also. In that letter, he has alleged that corruption was rampant in the Bharat Coking Coal Limited; that he had made written and verbal complaints about it to top officials of the Bharat Coking Coal Limited but no action was taken and instead he and his brother were stopped illegally from work without giving any notice. He further alleged that Mohan Khaitan, the Colliery Manager and S. S. Mitra, the Senior Personnel Officer, were leaders of dacoits and Mohan Khaitan used to get false bills in fictitious names prepared and then grab the money himself directly from the Cashier or pay clerk. He gave details of three such false bills, one dated May 27, 1974 for Rs. 460, a second dated 18-2-74 for Rs. 350 and the third without date for Rs. 108. He went on to allege that he refused to sign the payment of these bills but was threatened with grave consequences and, therefore, he signed the bills but reported the matter to higher officers and this resulted in his being stopped from work. He complained of corruption against S. S. Mitra also for taking bribes and finally he prayed for an independent enquiry by the C.I.D. or by the Dy. Commissioner, Dhanbad. Ext. W-92 is a letter that he sent to the General Manager, Area No. I on November 5, 1974 alleging induction of several persons and asking him to stop them from working. He has repeated the charge of corruption in his oral evidence and stated that Mohan Khaitan used to get fictitious bills prepared by him. He did not know that he was really preparing fictitious bills but some weeks later he discovered this fact when some members of the staff apprised him about it. He then made oral complaints to some officers. He made written complaint also later after he had been stopped from work. He then referred to the three fictitious bills mentioned above. He then says that the Vigilance Wing made an investigation but the whole thing was suppressed and as a repercussion he was stopped from work because of the fact that he had made a complaint. He goes on to state that he talked about it with the Senior Vigilance officer and protested

to him that he should have been called by him and his evidence recorded but the Senior Vigilance Officer told him that there was no point in involving high officers and that if he wanted to be benefited he should meet the Director, Personnel, through R. N. Sharma, M.P. but he refused to meet the Director, Personnel, as his relations with the officers of the Bharat Coking Coal Limited had become too much strained by then. In cross-examination, he has been unable to substantiate that any false bills were prepared. He said that some people had told him that the bills were false but he did not question them as to how they were calling these bills to be false. He questioned the attendance clerk also but the latter also said that he had no knowledge as to where the persons had worked for whom the false bills had been prepared. He went on to state that names of these persons were not entered in registers C, D or E but the Manager used to sign a slip for each payment. He had to admit that if a workman went on leave with wages or if he was sent out on colliery work, his attendance would not be marked in any register C, D or E and still payment would be made on the basis of a slip issued by the Manager. He made no complaint about these bills so long as he was in employment but modified it later and said that he went and complained to the Sub-Area Manager but he turned him out and he also used hot words to him in exchange. I do not think it safe to place reliance on his sweet-say. He is a highly interested witness. He entered employment in a surreptitious manner; he got his name entered in Ext. W-15 in a highly objectionable manner; he put his thumb impression although he is fairly educated; he kept quiet about the alleged false bills till he was stopped; he has no personal knowledge if the bills were false; he did not summon the Sub-Area Manager to prove his case; he complained of corruption only after he was stopped from work; and it will not be possible, therefore, to infer victimisation.

17. My award is that the action of the management of Bharat Coking Coal Limited in stopping Jagadamba Prasad Tiwary from work with effect from June 17, 1974 is justified and he is not entitled to any relief.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-20012/163/74-I RII/D III A]

S.O. 1219.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Akashkinaree Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh, and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th March, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 9 of 1976

(Ministry's Order No. L-20012/121/76-D.III(A),
Dt. 27-10-1976)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Akashkinaree Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad.

AND

Their Workmen

PRESENT : Mr. Justice K. B. Srivastava (Retd.)
Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. Prasad, Advocate, and Shri P. Burman, Jr. Law Officer.

For the Workmen—Shri Shankar Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 25th March, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the

Industrial Disputes Act has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal, namely :—

“Whether the action of the management of Akashinaree Colliery of Messrs Bharat Coking Limited, Post Office Katrasgarh, (District Dhanbad) in placing Shri Jai Shankar Prasad Yadav, Bhatta Supervisor, Soft Coke Bhatta in Clerical Grade II is justified? If not, to what relief is the said workman entitled and from which date?”

2. Usual notices were issued requiring the parties to file their respective written statements; and in response to that, the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh filed its written statement on December 31, 1976 and the Bharat Coking Coal Limited filed its written statement on January 10, 1977. The Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh also filed a rejoinder to the written statement of the Bharat Coking Coal Limited on January 29, 1977.

3. The case of the Mazdoor Sangh is that the workman concerned, namely, Jai Shanker Prasad Yadav was appointed as Bhatta Supervisor by the previous owner of West Katras Colliery long before its nationalisation and he continued to work as such even after nationalisation; that Jai Shankar Prasad Yadav was categorised by the Bharat Coking Coal Ltd. in the clerical Grade II whereas other Supervisors have been categorised in the clerical Grade I; that the grades have been revised since January 1, 1975; that the Mazdoor Sangh raised an industrial dispute with the Bharat Coking Coal Limited that there should be no discrimination and Jai Shankar Prasad Yadav should also be categorised in the clerical Grade I but this demand was turned down; that the Mazdoor Sangh then approached the Asst. Labour Commissioner (Central) but conciliation also failed on March 5, 1976; that the Asst. Labour Commissioner (Central) submitted a failure report to the Central Government on May 21, 1976 resulting in the present reference; that the duties assigned to Jai Shankar Prasad Yadav called for high skill, ability and experience and he deserves to be categorised in clerical Grade I; and hence it is prayed that he should be placed in clerical Grade I and suitable costs be also awarded against the Bharat Coking Coal Limited.

4. The Bharat Coking Coal Limited has pleaded that Jai Shanker Prasad Yadav was originally appointed as an Attendance Clerk in clerical Grade II; that the post of a Bhatta Supervisor has not been categorised in the report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry; that the duties of a Bhatta Supervisor are identical to the duties of a Loading clerk who has been categorised in the clerical Grade II in the report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry; that the duties of a Bhatta Supervisor do not involve the exercise of any skill higher than that of a Loading Clerk; that there are no technical or other qualifications prescribed for or required by a Bhatta Supervisor so as to entitle him to be categorised in grade I; and, therefore, the award be given against Jai Shanker Prasad Yadav.

5. In the rejoinder, the Mazdoor Sangh has only controverted the facts pleaded by the Bharat Coking Coal Limited and has taken no new pleas.

6. It is not disputed that Jai Shanker Prasad Yadav was appointed as an Attendance Clerk by the owner of the West Katras Colliery on May 1, 1971. This fact is also apparent from the register Form B Ext. M-2/1. West Katras Colliery was a non-coking coal mine. The management of all non-coking coal mines, with the exception of a few captive coal mines of the TISCO and IISCO, was taken over by Custodians on January 31, 1973 under Section 3 of the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973. This Ordinance was subsequently replaced by the Coal Mines (Taking over of Management) Act, 1973. All such mines, with the exceptions above-mentioned, were nationalised on May 1, 1973 under Section 3 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973. The Bharat Coking Coal Limited, which is a Government company, came to be vested with the right, title and interest of previous owners of all such coal mines. Four such non-coking coal mines were North Akashkinari, North Tentuliya, West Kailudi and Katras New. These four and West Katras were very small and un-economic coal mines. The Bharat Coking Coal Limited, therefore, merged these five mines into a bigger mine called the Akashkinari Colliery on August 1, 1973. The services of Jai Shanker

Prasad Yadav were taken over by the Bharat Coking Coal Ltd. when the management of West Katras Colliery was taken over on January 31, 1973. Jai Shankar Prasad has claimed that his basic wage on the date of his original appointment on May 1, 1971 was Rs. 150 per month but that does not appear to be correct. His basic wage was only Rs. 51 per month as will appear from the Bonus Register Ext. M-3, which bears his signature also. The minimum wage per day of a Time-Rater, in accordance with the report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry, was Rs. 5 per day. The month counted as 26 days for daily Time-Raters and, therefore, the Bharat Coking Coal Limited fixed the wages of Jai Shankar Prasad Yadav at Rs. 130 per month from August 1, 1973. This will appear from Ext. M-2. Jai Shankar Prasad Yadav, however, was really not a daily time-rated workman but an Attendance Clerk and he had, therefore, to be categorised in a clerical Grade. Such Grades appear on pages 75 and 76 of Chapter VIII of the report, Volume I, of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry. There were four such grades, vide paragraph 15 of Chapter VIII, namely, Special Grade : Rs. 305-15-425-20-505 plus 10 per cent attendance bonus; Grade I : Rs. 245-10-325-15-385 plus 10 per cent attendance bonus; Grade II : Rs. 205-7-275-10-325 plus 10 per cent attendance bonus; and Grade III : Rs. 180-5-230-7-265 plus 10 per cent attendance bonus. The Bharat Coking Coal Limited categorised Jai Shanker Prasad Yadav in Grade II in the scale of Rs. 205-325. Ext. M-2 also shows his categorisation in Grade II with the starting salary at the minimum of Rs. 205. The pay scales have been revised by the National Coal Wage Agreement dated December 11, 1974 which came into force on January 1, 1975. The old clerical Grade II now carries the pay scale of Rs. 378-18-522-24-570; and it is not disputed that Jai Shanker Prasad Yadav has been fixed in this revised Grade II.

7. Jai Shanker Prasad Yadav claims that his proper categorisation should be in the clerical Grade I. Appendix VI of Vol. II of the report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry has enumerated the persons who should be placed in clerical Grade I or II or III. The post of Attendance Clerks is given in Grade II and not under Grade I. The grade I has to be given to Head Clerks, Senior Cashiers, Storekeepers, Despatch Clerks, Audit Clerks, Stenographers, Comptometer operators, Loading Inspectors, Loading Superintendents, Coal Inspectors, Weigh Bridge Overseer, Gomostas and Lamp Room-in-Charge. Grade II, amongst others, is given to Attendance Clerks and Loading Clerks. The designation of Jai Shanker Prasad Yadav was Attendance Clerk and, therefore, he was properly categorised in the clerical Grade II.

8. The Akashkinari Colliery makes soft coke. Piece-Raters are employed to stack the excavated raw coal at specified places in the campus of the colliery. These Piece-Raters may be called Raw Coal Stackers. The stacked raw coal is then converted into soft coke by Time-Raters by the simple process of firing it and by extinguishing the fire when the smoke subsides. The disappearance of the smoke gives the signal that raw coal has become soft coke. The Bharat Coking Coal Limited appointed Jai Shanker Prasad Yadav as Bhatta Supervisor, Soft Coke Bhatta sometime in the year 1974. He claims the revised grade I in the scale of Rs. 442-22-618-30-678. It has been mentioned above that the post of a Bhatta Supervisor has not been categorised at all in the report of the Central Coal Wage Board for Coal Mining Industry. In paragraph 18 of Chapter VII of the report, Volume I, however, the following occurs :

“We are aware that there are some designations, i.e. other than those mentioned in Appendix XVI to the Majumdar Award which are not covered by our recommendations, as sufficient materials have not been placed before us to make any specific recommendations in respect of them. We would, therefore, recommend that these categories should be appropriately adjusted in the scales of pay recommended by us bearing in mind the nature of the duties performed by them and the responsibility attached to their job. In case of disputes arising from such categorisation we would recommend that the same should be settled by mutual negotiations between the managements and the representatives of the workmen at unit level.”

9. Ordinarily, it should be the exclusive function of the management to determine the skill, responsibility and efficiency that a workman must possess for purposes of proper classification and categorisation. This was, however, not done by mutual negotiations between the management and the

Mazdoor Sangh, and, therefore, the Tribunal has to see whether there is a case for the categorisation of Jai Shanker Prasad Yadav in the revised clerical Grade I.

10. MW-1 Ramesh Chandra Sharma is the Manager of the Colliery. He has stated that the designation of Jai Shanker Prasad Yadav continues to that of an Attendance Clerk but the job entrusted to him is the supervision of soft coke making. He has further stated that there can be no question of discrimination because there is no post of Bhatta Supervisor, Soft Coke Bhatta in any other colliery of the Bharat Coking Coal Limited who might be in Grade I. According to him, soft coke making is supervised in the other collieries of Bharat Coking Coal Limited by Loading Clerks whereas in the Akashkinari, the soft coke making is supervised by the Soft Coke Bhatta Supervisor. He goes on to state that Loading Clerks who supervise this work in other collieries are in clerical Grade II. He has then stated that a Loading Clerk has to supervise the work of coal loaders in trucks and wagons but the Loading Clerk is also a clerk in the clerical Grade II. He has further stated that no technical or any other qualification is either prescribed or necessary for supervision work. He even states that the stacking is done only in the 1st Shift between 9 a.m. and 5 p.m. by Coal Stackers who are Piece-Raters and Jai Shanker Prasad Yadav has to see that stacking is done properly. He has not necessarily to be present when stacked coal is fired or when the fire is extinguished. He has sworn that the job of firing and extinguishing is done by Time-Raters and there is no Supervisor to supervise their work. As against this, Jai Shanker Prasad Yadav has examined himself as WW-1. He has given some reasons why he is entitled to clerical Grade I and let me test the validity of the reasons. The first point made by him is that his duty is not only for 8 hours but it is a 24 hours duty. He was unable to substantiate it in his cross-examination. He had to admit that his duty hours are from 8 a.m. to 4 p.m. He has, however, added by saying that the Manager has directed that if necessity arises, he will have to supervise the work in night time also. No such suggestion was made to Ramesh Chandra Sharma in cross-examination. Assuming that some overtime work is taken, he would only become entitled to overtime allowance but he admits that he never put any written claim for any such allowance. He says that he made a verbal claim to the Manager but the Manager was not given the chance to deny this fact. The second point made by him is that he has to arrange for sufficient water for extinguishing the fire after raw coal becomes soft coke. In cross-examination he admitted that there is a 'talab' to store water for extinguishing the fire. There is an Electrician who runs the electric pump for pumping water which arrives at the stack in hose pipes. He has further admitted that in case of electricity failure, there is a stand-by diesel pumping set within 300 feet of the 'talab' and the Pump Khalasi pumps water by the diesel pumping set. The job of Jai Shanker Prasad Yadav is only to obtain a sanction order from the Manager for the issue of diesel from the Store Room to run the diesel pumping set and to account for the diesel so issued. The third point made by him is that if some workmen do not turn up, he has to report to the Manager and obtain his sanction for the engagement of casual labour or permanent workmen on overtime basis. The next point made by him is that if the raw coal is over-burnt, the responsibility for the loss is fixed on him. One stack ordinarily contains 40 or 50 tonnes of raw coal and if there is over-burning, some 20 or 25 tonnes of the coal becomes waste. He, however, admits that he was never charged for over burning of coal though at times there was over-burning. Lastly, he has stated that he has to supervise the firing and extinguishing process but Ramesh Chandra Sharma has denied that this is so. It was argued that one Nandlal in Jogidih Colliery of Bharat Coking Coal Limited also supervises the making of soft coke but he has been given Grade I and, therefore, Jai Shanker Prasad Yadav should also get that Grade. However, Jai Shanker Prasad Yadav had to admit that Nandlal is a Gomastah and according to Appendix VI of report, Vol. II of the Central Wage Board for Coal Mining Industry, a Gomastah has been categorised in clerical Grade I and; that being so, there is no discrimination as the Bharat Coking Coal Ltd. was bound to give Grade I to the Gomastah. All told, Jai Shanker Prasad Yadav is not doing any work which requires any supervisory responsibility. Indeed, it is not his case that he should be categorised in the technical or supervisory Grade. The work that he does is the routine work of a clerk involving no exercise of administrative power. He has not to take the attendance of the stackers working under him. He has not even the power to grant leave to them. It is true that some

general instructions were issued to him like Ext. W-3 to ensure that soft coke is manufactured properly or else he would be responsible for it and that he should attend a seminar for quality control on one day but these facts will not by themselves entitle him to be promoted to Grade I. Persons doing work of the same nature in respect of coal loading, i.e., supervision work of coal loaders, are in Grade II and there is no reason why Jai Shanker Prasad Yadav should get Grade I. Grade I is really meant for very senior hands like Head Clerks or Senior Cashiers or for persons who know short-hand and typing like stenographers etc. Jai Shanker Prasad Yadav started service only on May 1, 1971 and has not put in even six years service. He started on a salary of Rs. 51 per month and during the course of six years he is in the scale of Rs. 378-18-522-24-570. He should wait for his turn for Grade I in the scale of Rs. 442-22-618-30-678. Surely, vacancies will occur in Grade I in course of time and surely he will receive due consideration when the opportune time comes. At the moment, I do not feel that he is entitled to Grade I.

11. My award is that the action of the management of Akashkinari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited in placing Jai Shanker Prasad Yadav in Clerical Grade II is justified and he is not entitled to any relief.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

[No. I-20012/121/76-D III A]

New Delhi, the 14th April, 1977

S.O. 1220.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bastacolla Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th March, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 10 of 1976

(Ministry's Order No. L-20012/134/76-D III(A), Dt. 27-10-76)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bastacolla Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, Distt. Dhanbad

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice K. B. Srivastava (Retd.), Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Management—Shri S. N. Singh, Personnel Manager (CCWO), Shri A. A. Jafri, Dy. Personnel Manager (IR), and Shri P. K. Berman, Jr. Law Officer.

For the Workmen—Shri B. P. Sinha, Vice-President and Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 24th March, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal, namely :—

"Whether the action of the management of Bastacolla Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad, in dismissing Sarvashri Karu Dusadh, Trammer and Kailash

Dusadh, Line Mazdoor, from service, with effect from the 23rd December, 1975, is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?"

2. The parties have entered into a settlement which is an annexure to this award. The dispute between them has been amicably settled, and the settlement appears to be reasonable and fair.

3. My award is that the dispute stands settled by this settlement which is an annexure to this award and which shall form part of it.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In Reference No. 10 of 1976

Employers in relation to Bastacolla Colliery;

AND

Their Workmen represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

Joint Petition of Compromise Settlement

The humble petitioners, on behalf of the parties above named, most respectfully begs to state, that the instant dispute has been amicably settled between the parties, on the terms stated below:

Terms of Settlement:

1. The parties agree that Shri Karu Dusadh, and Karlash Dusadh, the concerned workman, will be reinstated in their respective posts, in any of the section/colliery of BCCL listed below, within 15 days of their reporting for duty to the General Manager, Area No. 9.
 - (a) Chanduari Section.
 - (b) Victory Section.
 - (c) Liberty Section.
 - (d) Bera Colliery.
2. The parties agree that the continuity of service of the workmen shall be maintained, and the period of their illness, from the date of dismissal to that of reinstatement, shall be treated as leave without pay for the purpose of calculating earned leave and bonus.
3. The parties agree that they shall have no other claim whatsoever, against each other, on account of the present dispute, which stands fully and finally resolved by this settlement.

The petitioners pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the above settlement, and to pass award, in terms thereof.

B. P. SINHA,
Vice-President, R.C.M.S.

For Management

1. Shri S. N. Singh,
Personnel Manager (CCWO),
B.C.C.L.
2. Shri A. A. Jafri,
Dy. Personnel Manager (IR),
B.C.C.L.
3. Shri P. K. Burman,
Jr. Law Officer,
B.C.C.L.

For Workmen.

1. Shri S. Bose,
Secretary, Rashtriya
Colliery Mazdoor Sangh.

Dated, the 24th March, 1977.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. I-20012/134/76-D III A]

S.O. 1221.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Govindpur Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th March, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 8 of 1976

(Ministry's Order No. L-20012/152/76/DIIIA, Dt. 27-10-1976)

PARTIES:

Employers in relation to the management of Govindpur Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad;

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice K. B. Srivastava (Retd.), Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri R. K. Yashroy, General Manager.

For the Workmen—Shri Kunwar Singh, Branch Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE: Bihar.

INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 24th March, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal, namely—

"Whether the action of the management of Govindpur Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, Distt. Dhanbad, in not regularising the following Bhattamen is justified? If not, to what relief is each workman entitled and from which date?"

S. No. Name of the workers.

1. Shri Raghu Deshwali
2. Shri Prayag Bhuia
3. Shri Mohan Rout
4. Shri Tuntun Mondal
5. Shri Chandrika Singh
6. Shri Nandu Prasad
7. Shri Prakash Rout
8. Shri Munilal Rai
9. Shri Damodar Singh
10. Shri Rameshwar Singh
11. Shri Suranjan Das
12. Shri Rambali Prasad
13. Shri Umesh Kumar Singh
14. Shri Lakshman Yadav
15. Shri Raghunath Singh
16. Shri Sri Ram Yadav."

2. The parties have entered into a mutual settlement whereby they have amicably settled their dispute, and the settlement appears to me to be proper, reasonable and fair.

3. My award is that the dispute between the parties stands settled by the settlement which is an annexure to this award and which shall form part of it.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In Reference No. 8 of 1976

Employers in relation to Govindpur Colliery

AND

Their Workmen represented by R C M S

Joint petition of Compromise Settlement

The Humble Petitioners on behalf of the parties above-named most respectfully beg to submit that instant dispute has been amicably settled between the Parties on the terms stated below :—

Terms of Settlement :

- 1 It is agreed by the Parties that S/Shri Raghuraj Deswari, Mohan Rout, Damodar Singh, Prakash Rout, Umesh Kumar Singh, Raghunath Singh, Tuntun Mondal, Nandu Prasad, Rameshwar Singh, Rambali Prasad, Lakshman Yadav, Sriram Yadav, Prayag Bhuia, Chandrika Singh and Munilal Rai shall be treated as permanent from 1-10-76.
- 2 It is agreed that S/Shri Chandrika Singh and Munilal Rai shall be allowed to resume their duties on and from the date of the settlement.
- 3 It is agreed that S/Shri Chandrika Singh and Munilal Rai shall have to join their duties within 15 days from the date of settlement.
- 4 It is agreed that if S/Shri Chandrika Singh and Munilal Rai do not join their duties within 15 days from the date of settlement and they do not show reasonable cause for non-joining of their duties to the management, they shall lose their claim over employment with the management.
- 5 It is agreed by the Union/Workmen that the claim of the rest of the workman listed below is given up by the Union.
(i) Shri Suranjan Das.
- 6 It is agreed that the parties shall have no further claim whatsoever against each other on this account and the present dispute stands finally and fully resolved as a result of this settlement.

The humble petitioners pray that Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the settlement and pass an award in terms thereof

1 Kunwar Singh,
(Branch Secretary).
R.C.N.S.
For the Workmen

1 R. K. Yashroy,
General Manager.
For the Employer.

Dated : 22-3-77.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-20012/152/76-D III-A]

S. H. S. IYER, Desk Officer

अम संशालय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1977

का० प्रा० 1222—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का .4) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 24 अप्रैल, 1977 को उक्त तारीख

के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 14 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्षेत्र	राजस्व थाना का नाम	राजस्व थाना सं०	जिला
वरियापुर ग्राम	मोतीहारी	196	मोतीहारी
तारकुलवा ग्राम	तार कुलिया	106	मोतीहारी
खोदानगर ग्राम	मोतीहारी	165	मोतीहारी
लुआहाला ग्राम	मोतीहारी	170	मोतीहारी
बलुआताल ग्राम	मोतीहारी	105	मोतीहारी

[सं० एम-38013/39/76-एन० प्राई०]

एम० एम० सहस्रनामन उप सचिव

New Delhi, the 16th April, 1977

S.O. 1222.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 24th April, 1977 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Bihar, namely :—

Area	Name of Revenue Thana	Number of Revenue Thana	District
Warapur Village	Motihari	196	Motihari
Tarkulva Village	Tarkulia	106	Motihari
Khojanagar Village	Motihari	165	Motihari
Luathaha Village	Motihari	170	Motihari
Balua Tal Village	Motihari	105	Motihari

[No. S-38013/39/76-HI]

S. S. RAHASRANAMAN, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1977

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा 16 अप्रैल, 1977 को बनायी गई निम्नलिखित अधिसूचना ग्राम जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

का० प्रा० 1223.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371ब के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हमने उपायुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तर्गों और निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, विस्तार मिक्किम राज्य पर करने हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त अधिनियमितियों में मिक्किम राज्य में ऐसी विधि जो प्रवृत्त नहीं है या ऐसा कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं है, के प्रति निर्देश का अर्थव्ययन उस राज्य की तत्समान प्रवृत्त विधि या तत्समान विद्यमान कृत्यकारी के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा।

परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि तत्समान ऐसा कृत्यकारी कौन है या यदि ऐसा तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चित कर सकेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) प्रत्येक अधिनियमिति के समुगत उपबन्ध, यदि कोई हों, में उसके प्रारम्भ की बाबत अन्तर्दिष्ट किसी बाग के होने हुए भी ऐसी प्रत्येक अधिनियमिति के उपबन्ध सिक्किम राज्य में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिमूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु किसी अधिनियमिति के विभिन्न उपबन्धों के लिये और सिक्किम राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे उपबन्ध में अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्वेश का अर्थान्वयन उस क्षेत्र में जहाँ वह प्रवृत्त किया गया है, उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्वेश के रूप में किया जाएगा।

अनुसूची

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम
1894	1	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
1973	46	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973
		बी० डी० जती उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
		[एफ० 11013/9/77-सिक्किम]
		के० एम० एल० छाबड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th April, 1977

The following notification made by the Vice-President, acting as President of India on the 16th April, 1977 is published for general information :—

S.O. 1223.—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the enactments specified in the Schedule annexed hereto subject to the modifications, if any, specified in that Schedule and the following further modifications, namely :—

(1) Any reference in the said enactments to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision, if any, of each such enactment for the commencement thereof, the provisions of each such enactment shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of any enactment and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

SCHEDULE

Year	No.	Short title
1894	1	The Land Acquisition Act 1894
1973	46	The Foreign Exchange Regulation Act 1973.

B. D. JATTI, Vice-President
Acting as President of India

[F. 11013/9/77-SKM]

K. M. L. CHHABRA, Joint Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1977

का० प्रा० 1224.—भारत रक्षा (स्वाधर संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण) नियम, 1971 के नियम 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम बहादुर सिन्हा, जिला और मज न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकार की अधिमूचना संख्या का० प्रा० 1035 तारीख 22 अगस्त, 1975 के द्वारा, गृह मंत्रालय की अधिमूचना सं० जी० एम० आर० 1716 तारीख 13 दिसम्बर, 1962 के साथ पठित भारत रक्षा अधिनियम, 1962 (1962 का 51) की धारा 20 के अधीन अधिग्रहित जोन सं० 63, वार्ड सं० 9, सक्ति सं० 3 बी, मुजफ्फरपुर नगर में दुर्गभले भवन, जिसके ज्योरे उक्त अधिमूचना की अनुसूची में दिए गए थे, के संबंध में प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

और चूंकि उक्त माध्यस्थ श्री राम बहादुर सिन्हा ने माध्यस्थ कार्यवाही पूर्ण नहीं की और उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि में पंचाट नहीं किया है,

और चूंकि केन्द्रीय सरकार यह ठीक समझती है कि उक्त माध्यस्थ द्वारा पंचाट देने की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त माध्यस्थ श्री राम बहादुर सिन्हा द्वारा पंचाट देने की अवधि 31 अगस्त, 1977 तक बढ़ाती है।

[स० 19011/1/76-पौन IV]

आई० चौधुरी, सम्प्रदा निदेशक

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 14th April, 1977

S.O. 1224.—Whereas in exercise of the powers conferred by rule 10 of the Defence of India (Requisitioning and Acquisition of Immovable Property) Rules, 1971, Shri Ram Bahadur Sinha, District and Sessions Judge, Muzaffarpur, was appointed by the Notification of the Government of Bihar, No. S.O. 1035 dated the 22nd August, 1975, as arbitrator to determine the amount of compensation payable in relation to the two storied building in holding No. 63, ward No. 9, circle No. 3B, Muzaffarpur Town, details of which were set out in the Schedule to the said notification, requisitioned under section 29 of the Defence of India Act, 1962 (51 of 1962) read with Home Ministry Notification No. G.S.R. 1716 dated the 13th December, 1962;

And whereas the said arbitrator Shri Ram Bahadur Sinha has not completed the arbitration proceedings and given his award within the period specified in sub-rule (2) of rule 10 of the said rules ;

And whereas the Central Government thinks fit that the period for making the award by the said arbitrator should be enlarged;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (2) of rule 10 of the said rules, the Central Government hereby enlarges the period for making the award by the said arbitrator Shri Ram Bahadur Sinha till the 31st August, 1977.

[No. 19011(1)/76-Pol. IV]

I. CHAUDHURI, Director of Estates